



सत्य की उड़ान



समाचार



ईडी अफसरों पर स्ट-रुज केस: जवाब दाखिल करने में देरी पर सीएम हेमंत सोरेन पक्ष पर 10 हजार का जुर्माना

रांची, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में प्रतिवादी पक्ष (मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पक्ष) द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगे जाने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई।

जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने जवाब के लिए समय मांगे जाने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी पक्ष पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रतिवादी पक्ष तय समय-सीमा के भीतर अपना जवाब दाखिल करें. हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार के अनुसार, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर तक की है।

गौरतलब है कि जमीन घोटासे से जुड़े मामले में जांच के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से रांची के एससी-एसटी थाने में ईडी के तत्कालीन अधिकारियों कपिल राज, देवव्रत झा समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसमें अधिकारियों पर उत्पीड़न और अधिकारों के हनन का आरोप लगाया गया था. ईडी अधिकारियों ने इस एफआईआर और उसके आधार पर शुरू की गई कार्रवाई को रद्द कराने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. हाईकोर्ट के पूर्व के निर्देश के तहत अधिकारियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर पहले से ही रोक जारी है. इसी मामले में अदालत ने प्रतिवादी पक्ष से जवाब मांगा था, जिसमें देरी होने पर अदालत ने सख्ती दिखाते हुए हर्जाना लगाया है. अब मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी. हाईकोर्ट ने झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अर्थांरटी में जुर्माने की राशि जमा करने का निर्देश दिया है.

हाइवा की टक्कर से बाइक सवार की मौत, कुंडा गांव के युवक ने मौके पर तोड़ा दम

सारवां, एजेंसी। थाना क्षेत्र के सारवां-मधुपुर मुख्य मार्ग पर दौड़िया पंचायत के कुंडा खदान के समीप देर शाम सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गयी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घसको हाट से मोटरसाइकिल पर सवार कुंडा गांव निवासी संजय दास (लगभग 28 वर्ष) जा रहा था. इसी क्रम में हाइवा ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना की खबर पर समाजसेवी राजउद्दीन अंसारी के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. जानकारी मिलते ही सारवां पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार घायल संजय की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी थी.

पुलिस ने लोगों की भीड़ के बीच शव और हाइवा को अपने कब्जे में लिया. वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए देवघर भेज दिया. मिली जानकारी के अनुसार संजय घसको हाट से खरीदारी कर अपने घर जा रहा था. इसी क्रम में वह दुर्घटना का शिकार हो गया.

रांची में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार तीन युवकों की मौत

रांची, एजेंसी। जिला में खरसीदाग-नामकुम थाना क्षेत्र की सीमा पर अरविंद मिल के पास गुरुवार रात भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई. तीनों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे. इसी दौरान तेज रफ्तार और अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

इस दुर्घटना के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. बताया जा रहा है कि टक्कर मारने के बाद अज्ञात वाहन का चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही खरसीदाग पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से तीनों शवों को कब्जे में लिया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए रिस भेजा है. मृतकों की पहचान कर ली गई है. तीनों रांची के ओरमांडी थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन पहुंचे योगदा सत्संग आश्रम

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /



मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के परमहंस योगानंद पथ, बहु बाजार, चुटिया स्थित योगदा सत्संग आश्रम पहुंचे। उनके साथ विधायक कल्पना सोरेन भी थीं। मुख्यमंत्री ने स्वामी ईश्वरानंद जी और स्वामी निर्मलानंद जी से मुलाकात की और आश्रम की गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने श्री श्री परमहंस योगानंद जी का कक्ष, फोटो व पुस्तक गैलरी, लीची वेदी, स्मृति मंदिर, ध्यान मंदिर और उद्यान का भ्रमण किया। गैलरी में परमहंस जी और उनके शिष्यों द्वारा रचित पुस्तकें, डाक टिकट, फोटोग्राफ और उनके द्वारा इस्तेमाल की गई सामग्री संरक्षित है।

‘सबकी योजना सबका विकास’ अभियान के तहत सभी पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन

शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आजीविका सुदृढ़ीकरण सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित



तरीके से मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा तथा भवनहीन केंद्रों के लिए नए भवन का निर्माण होगा। साथ ही, बच्चों एवं धात्री माताओं के पोषण व विकास हेतु उपयोगी सामग्री सुनिश्चित की जाएगी। साथ में विद्यालयों में नवीन भवन, अतिरिक्त क्लास रूम, चहारदीवारी

और किचन शेड का निर्माण होगा। डिजिटल व आईसीटी उपकरण, स्मार्ट शिक्षण संसाधन, खेल सामग्री, लाइब्रेरी, आरओ वाटर कूलर तथा सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराकर विद्यालयों को ई-स्मार्ट मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण व आजीविका प्रोत्साहन के लिए

दीदी समूहों के स्वरोजगार और आय वृद्धि के लिए वर्किंग शेड का निर्माण, आवश्यक मशीनरी व उपकरण, कौशल विकास प्रशिक्षण और उत्पादों के विपणन हेतु बाजार लिंकेज की व्यवस्था की जाएगी। वहीं कृषि को बढ़ावा देने तथा वर्षा पर निर्भरता कम करने के लिए नदी, तालाब व नालों से खेतों तक पानी

पहुंचाने के लिए पंप, पाइपलाइन व विद्युत युक्त लिफ्ट सिंचाई योजनाएं स्थापित की जाएंगी। हर घर स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए सभी टोलों व मोहल्लों में सौर ऊर्जा आधारित ईएसआर तथा पाइपलाइन जलापूर्ति व्यवस्था का विस्तार किया जाएगा एवं पुरानी संरचनाओं का जीर्णोद्धार होगा। पंचायतों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों व युवाओं के लिए आधुनिक अध्ययन कक्ष, पुस्तकें, समाचार पत्र, कंप्यूटर, इंटरनेट और आवश्यक मानव संसाधन युक्त पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। जबकि किसानों, स्वयं सहायता समूहों और छोटे व्यापारियों के उत्पादों की बिक्री के लिए व्यवस्थित शेड, स्टॉल, पेयजल, शौचालय व बिजली युक्त हाट-बाजार तैयार किया जाएगा।

विशेष ग्राम सभा में जल संरक्षण व तालाब जीर्णोद्धार, स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, कौशल विकास केंद्र, सड़क संपर्क, सरकारी परिसरों की सुरक्षा, विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के शैक्षणिक एवं बौद्धिक विकास के लिए आयु-अनुरूप शिक्षण-अधिगम सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

विशेष ग्राम सभा में सभी सदस्यों ने इन प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध रूप से लागू करने का संकल्प लिया, जिससे पंचायत को एक आत्मनिर्भर और आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित किया जा सके। विशेष ग्राम सभा में संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला परियोजना प्रबंधक मो. तौहिद आलम, पंचायतों के वीएलई, जल संहिया, सेविका, जेएसएलपीएस की दीदीयां सहित सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे।

जरूरतमंद मरीज के लिए ‘समर्पण एक नेक पहल’ की तत्परता: उपलब्ध कराया गया 2 यूनिट रक्त

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

धनबाद: जरूरत के समय रक्त उपलब्ध कराकर मरीजों की मदद करने की दिशा में सामाजिक संस्था ‘समर्पण एक नेक पहल’ लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसी क्रम में संस्था की पहल पर पाटलिपुत्रा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, धनबाद में इलाजरत एक मरीज के लिए 2 यूनिट बी-पॉजिटिव (B+) रक्त श्रीनिवास ब्लड सेंटर, धनबाद से उपलब्ध कराया गया।



सुनिश्चित कराई। वहीं, ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता बनाए रखने और भविष्य में किसी अन्य जरूरतमंद मरीज को आपातकालीन परिस्थिति में मदद करने के उद्देश्य से संस्था के सक्रिय सदस्य गुप्तीमति सिंह ने

स्वयं एक यूनिट रक्तदान किया। संस्था के पदाधिकारियों ने इस अवसर पर कहा कि रक्तदान केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद के जीवन को बचाने का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माध्यम है। संस्था का सदैव यह प्रयास रहता है कि आपातकालीन परिस्थितियों में रक्त की कमी के कारण किसी भी मरीज या उसके परिजनों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

‘समर्पण एक नेक पहल’ संस्था ने समाज के सभी स्वस्थ एवं योग्य लोगों से नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील की है, ताकि रक्त के अभाव में किसी का जीवन संकट में न पड़े। ‘एक यूनिट रक्त – किसी की जिंदगी को उम्मीद। रक्तदान करें, जीवन बचाएं।’

सत्य, ईमानदारी और सादगी का प्रतीक है राष्ट्रपिता का जीवन - उप विकास आयुक्त

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

धनबाद: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157 वीं जयंती तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122 वीं जयंती के अवसर पर उप विकास आयुक्त सन्नी राज, सिटी एसपी ऋत्विक् श्रीवास्तव, अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश बारगे समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों ने सिटी सेंटर पर स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद सभी पदाधिकारियों ने गांधी सेवा सदन में राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उप विकास आयुक्त ने गांधी सेवा सदन के



पुस्तकालय को देखा। गांधी सेवा सदन से सभी पदाधिकारी खादी ग्रामोद्योग संघ पहुंचे। यहां राष्ट्रपिता तथा पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि दी। उन्होंने चरखा भी चलाया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि

पूज्य बापू का जीवन और उनके आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। उनकी अहिंसक नीतियों, नैतिक आधारों, अद्भुत नेतृत्व क्षमता ने और अधिक लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने सभी धर्मों को एक समान मानने, सभी भाषाओं का सम्मान करने, पुरुषों और महिलाओं को बराबर का दर्जा देने और दलितों-गैर दलितों के बीच की युगों से चली आ रही खाई को पाटने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता अपने अहिंसा के सिद्धांत के लिए सार्वभौमिक रूप से पूजनीय हैं। उन्होंने शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा का उपयोग करके भारत को आजादी दिलाई। उनका जीवन सत्य, ईमानदारी और सादगी का प्रतीक

है। उन्होंने कहा इसी प्रकार मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणास्रोत बना रहेगा। वे असाधारण इच्छाशक्ति वाले एक शानदार विचारक थे। जिन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों को बड़ी सरलता से न सिर्फ पार किया है बल्कि सभी के लिए प्रेरणा भी बने हैं। उन्हें आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के लिए देश की आकांक्षाओं में उनके योगदान के लिए एक उत्कृष्ट राजनेता के रूप में माना जाता है। मौके पर उप विकास आयुक्त सन्नी राज, सिटी एसपी ऋत्विक् श्रीवास्तव, अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश बारगे, ट्रैफिक डीएसपी, सहायक नगर आयुक्त, नजारत उप समाहर्ता सहित अन्य लोग मौजूद थे।

उपायुक्त ने गांधी जयंती पर राष्ट्रपिता को दी श्रद्धांजलि

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

रांची | गांधी जयंती के अवसर पर जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजन्त्री ने मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन, पुलिस अधीक्षक यातायात राकेश सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर पारस राणा, सख्त सदर कुमार रजत, प्रशिक्षु हूट आस्था शरण, अपर जिला दंडाधिकारी धनंजय, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडे सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी बापू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।



शहीद शेख भिखारी की जयंती पर हजारीबाग में होगा कार्यक्रम, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का आयोजन

हजारीबाग, एजेंसी। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की हजारीबाग जिला इकाई की ओर से शहीद शेख भिखारी की जयंती के अवसर पर 4 अक्टूबर 2026 को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम पगमिल स्थित होटल ग्रैंड पैलेस मैरेज हॉल में सुबह 11 बजे से शुरू होगा. आयोजन में संगठन के राष्ट्रीय, प्रदेश और प्रमंडल स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे. संगठन के अनुसार कार्यक्रम के दौरान शहीद शेख भिखारी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ कार्यक्रमों में शामिल भी आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम की पुष्टि को लेकर प्रकाशित स्थानीय रिपोर्ट में भी 4 अक्टूबर को होटल ग्रैंड पैलेस में सम्मेलन की जानकारी दी गयी है.

ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष मो. जहांगीर अंसारी ने कहा कि शेख भिखारी ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी. संगठन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार उनका जन्म 2 अक्टूबर 1819 को वर्तमान रांची जिले के खुर्दिया क्षेत्र में हुआ था. वे टिकैत उमरांव सिंह के साथ अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष से जुड़े थे. झारखंड सरकार भी



शेख भिखारी और टिकैत उमरांव सिंह को 1857 के संघर्ष के शहीदों के रूप में स्मरण करती रही है. शेख भिखारी के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को कार्यक्रम में याद किया जाएगा. संगठन के अनुसार उन्होंने चूटपालू घाटी में अंग्रेजी सेना के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी. झारखंड पर्यटन विभाग भी शेख भिखारी से जुड़े ऐतिहासिक स्थल को राज्य की स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत से जोड़ता है. जिला अध्यक्ष मो. जहांगीर अंसारी ने झारखंड

सरकार से शहीद शेख भिखारी के नाम पर छत्रवृत्ति योजना शुरू करने की मांग की है. उन्होंने विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम में उनकी जीवनी और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को शामिल करने की मांग भी रखी. उन्होंने कहा कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत है. कार्यक्रम में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मो. फिरोज अहमद अंसारी के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष हाजी मंजूर अहमद अंसारी, राष्ट्रीय

महासचिव सगीर अहमद अंसारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी इदरीस अंसारी, राष्ट्रीय सचिव डॉ. अनवर हुसैन, प्रदेश अध्यक्ष आबिद अली सहित कई पदाधिकारियों के शामिल होने की जानकारी दी गयी है. प्रमंडल स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. जयंती समारोह के साथ आयोजित होने वाले कार्यक्रमों सम्मेलन में संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी. जिला अध्यक्ष ने प्रमंडल के मोमिन समाज के लोगों से कार्यक्रम में शामिल होकर शहीद शेख भिखारी को श्रद्धांजलि अर्पित करने की अपील की है. स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज अहमद के दौर के दौरान हजारीबाग में संगठन के सम्मेलन का कार्यक्रम तय है. कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मो. बाबर अंसारी और मो. तस्लीम अंसारी के नेतृत्व में आयोजन कमेटी गठित की गयी है. इसमें मो. सलीम रजा, मो. आबिद अंसारी अधिवक्ता, मो. आफताब आलम, मो. सिराज अंसारी, मो. फिरोज अंसारी, मो. रब्बानी, मो. मुनाजिर और मो. एजाज समेत अन्य लोगों को शामिल किया गया है. कार्यक्रम की तैयारियों की निगरानी राष्ट्रीय सचिव डॉ. अनवर हुसैन कर रहे हैं.



50 वैगन बोल्टर भी नहीं रोक सके गंगा नदी का कटाव

साहिबगंज, एजेंसी। गंगा नदी के बड़े हुए जलस्तर और उससे हो रहे कटाव के कारण साहिबगंज में रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. सकरीगली-महाराजपुर के बीच रेललाइन के किनारे कटाव की वजह से साहिबगंज-बरहड़वा रेलखंड के डाउन लाइन पर गुरुवार को तीसरे दिन भी ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा. कटावरोधी कार्य गुरुवार को भी जारी रहा, लेकिन गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने की वजह से वह सफल नहीं हो पा रहा है.

ऐसे में शुक्रवार को भी पैसेंजर ट्रेनों को रद्द तथा एक्सप्रेस ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया गया है. रेलवे की मानें तो गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने से कटावरोधी कार्य में समस्या आ रही है. वहां पर गुरुवार को 45 फीट पानी मापा गया. जलस्तर अभी बढ़ रहा है. करीब सौ फीट में यह स्थिति है.

मंगलवार और बुधवार को करीब 50 वैगन बोल्टर डाला गया था, जो नीचे चला गया है. ऐसे में रेलवे के समक्ष चुनौती कठिन है. रेलवे ने जहाज के माध्यम से वहां बोल्टर गिराने की योजना बनायी थी. इसके लिए जहाज संचालकों से संपर्क किया गया, लेकिन कोई भी संचालक अपना जहाज वहां ले जाने को तैयार नहीं है. ऐसे में ट्रेनों का परिचालन शुरू होने में समय लग सकता है. सब कुछ ठीक ठाक रहा तब भी तीन से चार दिन उसे भरने में लगेगा. ऐसे में पांच अक्टूबर के बाद ही परिचालन शुरू होने की उम्मीद जतायी जा रही है.

हालांकि, इस संबंध में रेलवे का कोई अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है. उधर, स्थिति का जायजा लेने के लिए डीआरएम शुक्रवार को वहां पहुंचेंगे. बताया गया कि गुरुवार को स्लीपर्स को लोहे की जाली में डालकर गड्ढे में गिराया गया.

इधर, शुक्रवार तक 56 पैसेंजर व आठ मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द तथा 29 ट्रेनों को डायवर्ट किया जा चुका है. ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस व आटो-टोटो चालकों द्वारा मनमाना भाड़ा वसूला जा रहा है.

जमशेदपुर में फिर से गोलीबारी, एक युवक को लगी गोली, डीजीपी के जाने के 12 घंटे के अंदर हुई वारदात



जमशेदपुर, एजेंसी। शहर के सीतारामडेर थाना इलाके में कल देर रात अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की. इस घटना में एक युवक को गोली लगी है. पुलिस अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है. जमशेदपुर में अपराधियों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं. पिछले एक हफ्ते में हुई कई अपराधिक घटनाओं की वजह से शहर चर्चा का विषय बना हुआ है. गुरुवार को झारखंड की छत्तक तदाशि मिश्रा ने जमशेदपुर में बढ़ते अपराधों को लेकर समीक्षा बैठक की थी और अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे. फिर भी, छत्तक के जाने के सिर्फ 12 घंटे के भीतर ही बेखौफ अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे दी.

यह घटना कल देर रात सीतारामडेर थाना इलाके के बाराद्वारी में हुई. हमलावरों ने चार राउंड फायरिंग की. इस घटना में आबिद हुसैन नाम के युवक को गोली लगी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया.

जानकारी के मुताबिक, आबिद अपने घर के सामने दोस्तों के साथ बैठा था, तभी उनके बीच कहासुनी हो गई. आरोप है कि विवाद के बाद एक युवक स्कूटर पर आया और आबिद हुसैन पर फायरिंग कर दी. आबिद के बाएं हाथ में गोली लगी. जानकारी के अनुसार, कुल चार राउंड फायरिंग हुई. दो राउंड हवा में चलाए गए, जबकि दो गोलियां आबिद को लगीं. घटना की सूचना मिलने पर सीतारामडेर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल से खोखे बारमद किए हैं और फायरिंग में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए पूछताछ शुरू कर दी है.

खनिज सेस पर झारखंड सरकार का बड़ा दांव, एमएमडीआर संशोधन को दरकिनार कर वसूली जारी रखने की तैयारी क्या बोले वित्त मंत्री

रांची, एजेंसी। झारखंड में खनिजों पर सेस की वसूली को लेकर राज्य सरकार और केंद्र के बीच टकराव और बढ़ने के संकेत हैं. जानकारी के मुताबिक, राज्य की राजस्व संवर्धन समिति ने केंद्र के नए एमएमडीआर संशोधन के बावजूद खनिजों पर सेस की वसूली जारी रखने के फैसले पर मुहर लगाई है. जानकारी के मुताबिक, वित्त सचिव की अध्यक्षता में मंगलवार को राजस्व संवर्धन समिति की बैठक हुई थी, जिसमें खान, नगर विकास, परिवहन, पथ निर्माण और भू राजस्व विभाग में राजस्व बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई थी. इसमें बकाया परिवहन टैक्स की वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने और दूसरे राज्य से लघु खनिज लंदे गाइडों के झारखंड में प्रवेश पर शुल्क वसूली पर भी मंथन हुआ था. झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि उन्हें राजस्व संवर्धन समिति के इस फैसले की आधिकारिक जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर समिति ने एमएमडीआर एक्ट में किए गए संशोधन को दरकिनार करते हुए खनिजों पर सेस की वसूली जारी रखने का निर्णय लिया है, तो यह स्वागत योग्य कदम है. उन्होंने फिर दोहराया कि इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी. इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार पर मनमाने तरीके से कानून में बदलाव करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राज्यों के खनिज अधिकारों पर सेस लगाने के अधिकार को मान्यता दी थी. जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय संविधान पीठ के बहुमत ने भी राज्यों के खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने की शक्ति को मान्यता दी थी. मंत्री के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इसके बाद एमएमडीआर कानून में संशोधन कर राज्यों की खनिजों पर सेस लगाने की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया है. उनका कहना है कि संशोधन में 'खनिज युक्त भूमि' से जुड़े प्रावधानों को शामिल किया गया है, जबकि भूमि पर राज्य का अधिकार होता है. बता दें कि एमएमडीआर एक्ट में संशोधन के बाद 13 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस पर विचार करने का आग्रह किया था. उन्होंने इकोनामिक सर्वे 2025-26 का हवाला देते हुए कहा था कि खनन से मिलने वाला राजस्व 2024-25 में राज्य के अपने गैर कर राजस्व का करीब 84.9% था.

नक्सल अभियान में एक्सपर्ट अधिकारियों की हुई है पलामू में तैनाती, खास इलाकों को किया गया टारगेट

पलामू, एजेंसी। झारखंड में नक्सलियों का लगभग सफाया हो चुका है. गिने-चुने छह के करीब इनामी माओवादी बचे हुए हैं. जिन्हें टारगेट पर लेकर सुरक्षाबल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं. ये सभी माओवादी झारखंड के पलामू रेंज में मौजूद हैं. इसलिए अब पलामू रेंज में सुरक्षाबल नक्सलियों के खिलाफ अंतिम दौर की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं.

हाल ही में झारखंड पुलिस के वरीय अधिकारियों की हाइ लेवल बैठक हुई. जिसमें सभी जिलों के एसपी को टारगेट दिया गया है कि तीन महीने के अंदर सभी इलाकों को नक्सलियों से पूरी तरह मुक्त कर देना है. इसी टारगेट पर पलामू पुलिस भी जोर-शोर से लगी हुई है. नक्सलियों से जुड़ी हर एक जानकारी इकट्ठा की गयी है.

पलामू रेंज में बिहार-झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में माओवादी छिपे हुए हैं. इसे लेकर बिहार और झारखंड के पुलिस अधिकारियों के बीच भी बैठक हुई और रणनीति तैयार की गई. इस रणनीति के तहत पुलिस ने खास योजना तैयार किया है. झारखंड-बिहार सीमावर्ती इलाके के कई गांवों और जंगलों को टारगेट पर लिया गया है. पुलिस को भरोसा है कि इन्हीं गांव और जंगलों में माओवादी छिपे हुए हैं.

इसी कड़ी में पलामू में नक्सल अभियान में एक्सपर्ट अधिकारियों की तैनाती हुई है. पलामू रेंज के अंतर्गत पलामू, गढ़वा एवं लातेहार जिला आते हैं. 2024 में



पलामू को नक्सली मुक्त घोषित किया गया था, जबकि 2026 में गढ़वा भी नक्सल मुक्त के गाइडलाइन पर आ गया है. हालांकि, पूरे झारखंड में सबसे अधिक पलामू रेंज में ही इनामी नक्सल बचे हुए हैं. अगर इन नक्सलियों के खिलाफ अभियान सफल होता है तो पूरा पलामू रेंज नक्सलमुक्त हो जाएगा. पलामू के इलाके में 15 लाख के इनामी माओवादी नितेश यादव के नेतृत्व में माओवादियों का बड़ा दस्ता सक्रिय है. वहीं पलामू और लातेहार में 10 लाख के इनामी माओवादी मनोहर गंडू के

नेतृत्व में नक्सली सक्रिय हैं. लातेहार और गढ़वा के सीमावर्ती इलाके में पांच लाख के इनामी राजू भूइयां के नेतृत्व में दस्ता सक्रिय है. जबकि पलामू में 10 लाख के इनामी शशिकांत गंडू के नेतृत्व में दस्ता सक्रिय है. शशिकांत गंडू के नेतृत्व में झारखंड में टीएसपीसी का एक मात्र दस्ता सक्रिय है.

नितेश यादव के पास पूरे झारखंड में सबसे बड़ा माओवादियों का दस्ता है. झारखंड पुलिस की वेबसाइट के अनुसार, पलामू रेंज में छह इनामी नक्सली सक्रिय हैं.

झारखंड को डिजिटल हेल्थ में आगे ले जाने की तैयारी, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया रोडमैप



रांची, एजेंसी। झारखंड डिजिटल हेल्थ कॉन्क्लेव-2026 का गुरुवार को समापन हो गया. दो दिवसीय कॉन्क्लेव में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को तकनीक आधारित बनाने, ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों तक विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने तथा डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा हुई. समापन समारोह में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि यह आयोजन केवल दो दिनों का कार्यक्रम नहीं, बल्कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में नई शुरुआत है. कॉन्क्लेव का आयोजन 30 सितंबर से एक अक्टूबर तक रांची के बीएनआर चाणक्य होटल में किया गया.

डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि दुनिया जिस

गति से हाइटेक तकनीक अपना रही है, झारखंड भी उसी गति से आगे बढ़ेगा. उनका लक्ष्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार करना है, ताकि राज्य के लोगों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे राज्यों का रुख कम करना पड़े. उन्होंने कहा कि गरीब मरीजों के लिए बाहर जाकर इलाज कराना आसान नहीं है. इसलिए ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित करने पर जोर है, जिसमें आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण इलाज राज्य के भीतर ही उपलब्ध हो.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पीएचसी, सीएचसी, रेफरल अस्पताल, सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है. आईसीयू, वेंटिलेटर, एमआरआई, सीटी स्कैन और रेडियोलॉजी जैसी सुविधाओं के

विस्तार पर ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से स्वास्थ्य सेवाओं में मौजूद कमियों को दूर करने और विशेषज्ञ चिकित्सा की पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा. कॉन्क्लेव में टेली-आईसीयू और टेली-रेडियोलॉजी को ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में सामने रखा गया. पहले चरण में चार जिलों में 10-बेड वाले टेली-आईसीयू की शुरुआत की गई है, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक दूर से मरीजों की निगरानी और चिकित्सकीय सलाह दे सकते हैं. राज्य सरकार ने आने वाले समय में इस सुविधा का अन्य जिलों तक विस्तार करने की योजना भी बताई है.

कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, 10-बेडड टेली-आईसीयू, एचआरआईएस पोर्टल और झारखंड ई-हेल्थ पोर्टल का शुभारंभ किया गया. इन पहलों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना और अस्पतालों में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाना है. डिजिटल हेल्थ सेवाओं को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जोड़ने पर भी चर्चा हुई. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों का विकल्प बनना नहीं, बल्कि उनकी क्षमता और पहुंच को मजबूत करना होना चाहिए. एआई की मदद से रिपोर्ट के विश्लेषण और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन अंतिम चिकित्सकीय निर्णय प्रशिक्षित डॉक्टरों की निगरानी में ही होना चाहिए. कॉन्क्लेव में एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को लेकर भी विशेषज्ञों ने प्रस्तुतियां दीं.

लखनऊ जाने वाले यात्रियों के लिए राहत, आदित्यपुर से चलेगी स्पेशल ट्रेन

जमशेदपुर, एजेंसी। त्योहारों और धार्मिक यात्राओं के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लखनऊ और आदित्यपुर के बीच स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. ट्रेन संख्या 04218/04217 लखनऊ-आदित्यपुर-लखनऊ स्पेशल के परिचालन से यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी. ट्रेन लखनऊ से 10 अक्टूबर को रवाना होगी, जबकि आदित्यपुर से इसकी वापसी यात्रा 15 अक्टूबर को निर्धारित है. ट्रेन संख्या 04218 लखनऊ से 10 अक्टूबर

को दोपहर 12:05 बजे रवाना होगी. रायबरेली, अमेठी, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम, गया, गोमो, भोजपुरीह, अनारा, पुरलिया और चांडिल होते हुए अगले दिन सुबह 7:10 बजे आदित्यपुर स्टेशन पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 04217 आदित्यपुर से 15 अक्टूबर को सुबह 11:10 बजे खुलेगी. चांडिल, पुरलिया, गोमो, गया और वाराणसी के रास्ते अगले दिन सुबह 7 बजे लखनऊ पहुंचेगी. यह स्पेशल ट्रेन कुल 22 कोचों के साथ संचालित होगी. इसमें 18 स्लीपर व जनरल

कोच, दो थर्ड एसी कोच और दो एसएलआरडी कोच शामिल होंगे. इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली यह ट्रेन कुल 868 किलोमीटर की दूरी तय करेगी.

आदित्यपुर से खुलने के बाद ट्रेन दोपहर 12:08 बजे चांडिल, 1:05 बजे पुरलिया और शाम 3:50 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो पहुंचेगी. इसके बाद शाम 6:38 बजे गया और रात 11:55 बजे वाराणसी पहुंचेगी. इस विशेष ट्रेन के परिचालन से निर्धारित मार्ग के यात्रियों को भी यात्रा के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा.

दुर्गा पूजा से पहले बीएसएल कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

मिलेगा बंपर बोनस, ट्रेनी के भी खाते में आएंगे 25600 रुपये

बोकारो, एजेंसी। बीएसएल सहित सेल कर्मचारियों को लंबे अरसे बाद दुर्गापूजा से पहले बोनस मिलेगा. 11 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ दुर्गापूजा पूजा शुरू होगी. इससे पहले ही कर्मचारियों के खाते में बोनस की राशि पहुंच जायेगी. बोनस निर्धारण को लेकर गुरुवार को नयी दिल्ली में एनजेसीएस की बैठक हुई. बैठक में सेल प्रबंधन ने कर्मचारियों को 32,000 रुपये और ट्रेनीज को 25,600 रुपये बोनस देने की बात कही. इस पर सभी यूनियन नेताओं ने सहमति जताते हुए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये.

यूनियन की ओर से इस बार 40,500 रुपये बोनस की मांग की गयी थी. इसके मुकाबले प्रबंधन की ओर से तय राशि पर समझौता हुआ है. बीएसएल में कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं को दुर्गापूजा से पहले बोनस



की राशि मिलने से उनके बीच उत्साह है. बोकारो स्टील प्लांट के कुल 8741 कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं को बोनस का लाभ मिलेगा. बोनस की राशि 10 अक्टूबर से पहले कर्मचारियों के खाते में पहुंचने की बात कही गयी है. यानी भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद दुर्गापूजा से पहले ही राशि खाते में आ जायेगी.

वर्ष 2025 में कर्मचारियों को 29,500

रुपये और प्रशिक्षुओं को 23,600 रुपये बोनस मिला था. वर्ष 2024 में कर्मचारियों के खाते में 26,500 रुपये और 2023 में 23,000 रुपये बोनस की राशि दी गयी थी. बीएसएल कर्मचारियों को बोनस मिलने का असर बोकारो-चास के बाजार पर भी पड़ने की उम्मीद है. बाजार को बोनस की राशि का बेसब्री से इंतजार है. कर्मचारियों और उनके परिवारों ने पूजा की खरीदारी को

रांची की मोनिका दुबई में बंधक, एक्टिव हुआ विदेश मंत्रालय, एफआईआर भी दर्ज

रांची, एजेंसी। राजधानी रांची के छोटा घाघरा इलाके की रहने वाली मोनिका को नौकरी दिलाने के नाम पर दुबई भेजे जाने के बाद कथित तौर पर बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। परिवार का आरोप है कि दुबई पहुंचने के बाद मोनिका को अलग-अलग घरों में काम करने के लिए भेजा गया और उसके साथ प्रताड़ना की गई। बेटी की सुरक्षित वापसी के लिए मां ने विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है।

बेटी को बेहतर जिंदगी देने का सपना हर मां देखती है। लेकिन रांची के छोटा घाघरा की रहने वाली रतना कच्छप ने अपनी बेटी को जिस उम्मीद के साथ विदेश भेजा था, आज वही उम्मीद चिंता और बेबसी में बदल गई है। बेटी को अच्छी नौकरी, भोजन और रहने की सुविधा का भरोसा दिया गया था। मां को लगा था कि बेटी विदेश में मेहनत कर अपना भविष्य संभरेगी। लेकिन आरोप है कि नौकरी के इस सुनहरे सपने के पीछे ऐसा जाल बिछा था, जिसमें फंसकर मोनिका आज दुबई में असहाय स्थिति में है। मां का आरोप है कि बेटी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, उससे घरेलू काम कराया गया और भारत लौटने की इच्छा जताने पर धमकियां दी गईं।

अब मां की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ इतनी है कि उसकी बेटी किसी तरह सुरक्षित अपने घर लौट आए। यह मामला रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र का है। रतना कच्छप की शिकायत पर 29 सितंबर 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत में दुबई और अजमान में नौकरी दिलाने के नाम पर कथित धोखाधड़ी, मानव तस्करी, बंधक बनाने, जबरन श्रम कराने और रंगदारी मांगने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि 22 अप्रैल 2026

को मोनिका ने प्रियंका के बताए खाते में फोननेपे के माध्यम से 5 हजार रुपये भेजे। उसे बताया गया कि आगे की यात्रा और टिकट की व्यवस्था एजेंसी करेगी। इसके बाद 5 मई को दिल्ली एयरपोर्ट से शारजाह जाने के लिए एमोनिका रवाना हुई। 6 मई को शारजाह पहुंचने पर एजेंसी की ओर से भेजे गए वाहन के चालक ने कथित तौर पर उसका मूल पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लिया।

शिकायत में बताया गया है कि 7 मई को मोनिका को अजमान स्थित एजेंसी के कार्यालय ले जाया गया। वहां रितेश और मोहम्मद मेराज अंसारी नामक व्यक्तियों ने कथित तौर पर अरबी भाषा में लिखे दस्तावेजों पर दबाव डालकर हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लिए। मोनिका अरबी भाषा नहीं जानती थी। ऐसे में उन दस्तावेजों में क्या लिखा था, यह भी उसके लिए समझना मुश्किल था।

आरोप है कि उसका मोबाइल लेकर प्रियंका के साथ हुई चट्टासएप बातचीत भी मिटा दी गई। इसके बाद वीडियो कॉल के जरिए उसे बताया गया कि मिलने के 2600 दिरहम का कर्ज लिया है। 25 मई तक रकम नहीं चुकाने पर जेल भेजने की धमकी दी गई।

एफआईआर में मां ने आरोप लगाया है कि मोनिका को मोहम्मद मेराज अंसारी के घर ले जाया गया, जहां उसे करीब एक महीने तक बंधक जैसी स्थिति में रखकर झाड़ू-पोछा, बर्तन और बाथरूम साफ करने का काम कराया गया। इसके बाद 22 जून को उसे बिना वैध वर्क परमिट के एक घर में देखाभाल के काम के लिए भेजे जाने का आरोप है। भाषा नहीं समझ पाने के कारण अगले दिन उसे वापस कार्यालय छोड़ दिया गया। जुलाई में भी उसे दूसरे घरों में काम के लिए भेजा गया।

लेकर अपनी-अपनी लिस्ट तैयार कर रखी है. बाजार से जुड़े लोगों के अनुसार, बोनस की राशि आने के बाद दुर्गापूजा के दौरान खरीदारी बढ़ती है. इस बार करीब 30 करोड़ रुपये बोनस के रूप में बोकारो-चास के बाजार में आने की उम्मीद जतायी जा रही है. इससे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान और अन्य पूजा खरीदारी को गति मिलने की संभावना है. अब कर्मचारियों के साथ बाजार के कारोबारियों को भी बोनस की राशि खाते में आने का इंतजार है. नयी दिल्ली में हुई एनजेसीएस की बैठक में विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधि और सेल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. जी. संजीवा रेड्डी, बोकारो से बीएन चौबे, बीएमएस से श्रीनिवास राव और रंजय कुमार, सीट् दुर्गापुर से ललित मोहन मिश्र, भिलाई से डीवीएस रेड्डी, एचएमएस से संजय वढावकर, बोकारो से राजेंद्र सिंह, एटक से विद्यासागर गिरी और बोकारो से रामाश्रय प्रसाद सिंह शामिल हुए.

संक्षिप्त	समाचार
	
बिहार में पहली बार बनेगी एविएशन पॉलिसी, सोनपुर और अजगैबीनाथ में बनेंगे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट	
पटना, एजेंसी। बिहार सरकार राज्य में हवाई सेवाओं को बढ़ाने के लिए एक नई नीति तैयार कराएगी. इसका मकसद केवल हवाई सफर की सुविधा बढ़ाना नहीं है, बल्कि विमान से जुड़े दूसरे कामों को भी बिहार में शुरू करने की संभावनाएं तलाशना है. इसमें विमानों की मरम्मत, उनकी देखभाल और पायलटों को ट्रेनिंग देने जैसी सुविधाएं शामिल हैं. नई नीति में सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम में नए एयरपोर्ट बनाने की योजनाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा. सरकार यह देखेगी कि इन जगहों पर एयरपोर्ट बनाने से बिहार को क्या फायदे हो सकते हैं और इनके जरिए विमान से जुड़े दूसरे कामों को कैसे बढ़ाया जा सकता है. इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि राज्य में पहले से मौजूद एयरपोर्ट का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए. निजी कंपनियां इस क्षेत्र में पैसा लगाएं, इसके लिए भी रास्ते तलाशे जाएंगे. फिलहाल विमानों की बड़ी मरम्मत और उनकी देखभाल के लिए बिहार को दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है. सरकार चाहती है कि आने वाले समय में राज्य में ही ऐसी सुविधाएं विकसित करने की संभावना बने. इससे विमान कंपनियों को मदद मिल सकती है और बिहार में नए काम शुरू होने का रास्ता खुल सकता है. इसके लिए पहले योजना तैयार होगी. इसके बाद यह तय होगा कि कौन-कौन सी सुविधाएं शुरू की जा सकती हैं और उन्हें विकसित करने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी. केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार के मुजफ्फरपुर, बीरपुर, वाल्मीकिनगर और सहरसा जैसे शहरों के एयरपोर्ट को विकसित करने का काम चल रहा है. नई नीति में इन एयरपोर्ट का बेहतर इस्तेमाल करने और वहां हवाई सेवाओं को बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार किया जाएगा. सरकार यह देखेगी कि इन एयरपोर्ट का इस्तेमाल कैसे बढ़ाया जा सकता है और उपलब्ध सुविधाओं का सही तरीके से उपयोग कैसे हो. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे से पटना रिग रोड तक, बिहार के रोड नेटवर्क को मिलेगी नई रफ्तार	
पटना, एजेंसी। बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को पटना में बैठक कर राष्ट्रीय राजमार्गों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की. किसी भी राज्य के विकास में बेहतर सड़क नेटवर्क की अहम भूमिका होती है. इससे लोगों की यात्रा आसान होने के साथ व्यापार, पर्यटन और उद्योगों को भी मदद मिलती है. बिहार में चल रही सड़क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम में तेजी लाने पर जोर दिया गया. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने और काम के दौरान आने वाली समस्याओं का जल्द समाधान करने की बात कही. बैठक में केंद्र और राज्य से जुड़ी कई प्रमुख सड़क योजनाओं की मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई. बैठक में पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे और मोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे जैसी बड़ी परियोजनाएं शामिल रही. इनके अलावा मुजफ्फरपुर-बरौनी फोरलेनिंग, दरभंगा-सुपौल हाईवे, खगड़िया-पूर्णिया, मुजफ्फरपुर-सोनबरसा और आमस-दरभंगा परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई. मुंगेर-मिर्जाचौकी, बाकरपुर-मानिकपुर-साहेबगंज कोरिडोर, सीवान-मशरख और डुमरिया घाट पुल से जुड़े कामों पर भी चर्चा हुई. इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच सड़क संपर्क बेहतर करना है.	

भागलपुर में गंगा पार करना हुआ आसान: आम यात्रियों, साइकिल और एंबुलेंस के लिए फ्री हुई जहाज सेवा

भागलपुर, एजेंसी। गंगा नदी के दोनों छोरों को जोड़ने वाले विक्रमशिला सेतु के मरम्मत और स्थायी पुनर्निर्माण कार्य के चलते जब से गाड़ियां बंद हुई हैं, तब से भागलपुर और नवागछिया के लाखों लोगों की थड़कनें तेज थीं। हर किसी के मन में बस यही चिंता सता रही थी कि अब गंगा नदी को पार करने में कितनी मुसीबतें डेलनी पड़ेंगी और जेब पर कितना बड़ा डका पड़ेगा।

अब जिला प्रशासन ने आम नागरिकों और यात्रियों की इस सबसे बड़ी चिंता को चुटकी में दूर कर दिया है। अपर समाहता की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में फेरी सेवा और जहाजों के आवागमन के लिए आधिकारिक दरों का ऐलान कर दिया गया है। सबसे राहत की बात यह है कि आम यात्रियों से टिकट का एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा।

स्थानीय लोगों और दैनिक यात्रियों के लिए प्रशासन का यह फैसला किसी वरदान से कम नहीं है। फेरी सेवा संचालित करने के लिए गठित समिति ने 9 विभिन्न एजेंसियों द्वारा दिए गए रेट्स की गहन समीक्षा की और जहाज संचालकों के साथ लंबी वार्ता की। पहले प्रति यात्री 35 रुपये तय करने की बात चल रही थी, लेकिन समिति ने फैसला लिया कि आम जनता पर इसका कोई आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा।

अब 35 रुपये प्रति यात्री का किराया आम लोगों को नहीं देना होगा, बल्कि जहाजों की लगान क्षमता के आधार पर सरकार स्वयं संचालकों को इसका भुगतान करेगी। इसके साथ ही साइकिल से सफर करने वाले आम मजदूरों और इमरजेंसी में मरीजों को ले जाने वाली एंबुलेंस के लिए भी फेरी सेवा पूरी तरह नि:शुल्क रखी गई है।

गंडक के उफान से सारण में तबाही, तटबंध टूटा, दर्जनों गांव जलमग्न, 3 मौत और 5 लापता

सारण, एजेंसी। सारण जिले के मकेर, पानापुर, तरैया, अमनौर, परसा, दरियापुर और दिघवारा समेत कई प्रखंडों में बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है. गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच पानापुर के सरीजा भगवानपुर गांव के समीप गुरुवार की सुबह करीब चार बजे सारण तटबंध टूट गया. तटबंध टूटते ही तेज रफ्तार से बाढ़ का पानी आसपास के दर्जनों गांवों में प्रवेश कर गया. इससे हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं और लोग घर छोड़कर सुरक्षित एवं ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं.

बाढ़ के पानी में डूबने से मकेर और पानापुर में तीन युवकों की मौत हो गयी, जबकि मकेर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पांच लोगों के लापता होने की सूचना है. प्रशासन और बचाव दल लगातार प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं.

पानापुर के सरीजा भगवानपुर के समीप गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के दबाव के कारण सारण तटबंध टूट गया. तटबंध टूटने के बाद पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही समय में सतजोड़ा, चकिया और भगवानपुर समेत कई रिहायशी इलाकों में पानी फैल गया. खेत भी जलमग्न हो गये हैं.

ग्रामीण अपने परिवार, जरूरी सामान और मवेशियों को लेकर ऊंचे एवं सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं. प्रशासन की ओर से भी नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गयी है.

मकेर के सुल्तानगंज में बाढ़ के पानी में डूबने से 30



वर्षीय बबन महतो की मौत हो गयी. बताया जाता है कि वह अपने मवेशी को बाढ़ के पानी से निकालकर सुरक्षित स्थान की ओर ले जा रहे थे. इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वह तेज धारा में बह गये.

ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें पानी से बाहर निकाला और इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी ले गये. वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पानापुर में भी बाढ़ के पानी ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. खजुरी गांव निवासी मंजय कुमार के 17 वर्षीय पुत्र सत्यम कुमार और चकिया गांव निवासी सुरेंद्र राय के पुत्र अनिल राय की डूबने से मौत हो गयी.

बताया जाता है कि दोनों युवक दो अन्य युवकों के

मधुबनी पेंटिंग ही नहीं, अरिपन भी है मिथिला की पहचान

मधुबनी, एजेंसी। मिथिला अपनी पान, मखान और मधुबनी पेंटिंग के लिए तो प्रसिद्ध है ही, यहां की अरिपन कला भी खास पहचान रखती है. अरिपन एक पारंपरिक लोककला है, जिसे आमतौर पर पर्व-त्योहार, पूजा और दूसरे शुभ अवसरों पर बनाया जाता है. इसे जमीन या आंगन में चावल के घोल से अलग-अलग आकृतियां बनाकर तैयार किया जाता है. समय के साथ अब इसे कागज पर भी बनाया जाने लगा है.

एक इंटरव्यू में मैथिल कलाकार चतुपानन झा बताते हैं कि अरिपन एक तरह की शुभ फर्श कला है, जिसे हर शुभ अवसर पर बनाया जाता है. इसके बिना कोई भी आयोजन पूरा नहीं माना जाता. हमारे समुदाय में यह परंपरा बहुत लंबे समय से चली आ रही है.

मिथिला में अरिपन का इस्तेमाल अलग-अलग धार्मिक और पारंपरिक अवसरों पर किया जाता है. किस मौके पर अरिपन बनाया जा रहा है, उसके अनुसार उसकी आकृति और उसमें बनाए जाने वाले प्रतीक भी बदल सकते हैं. इसलिए इसे केवल एक खास डिजाइन तक सीमित



नहीं माना जा सकता. परंपरागत रूप से अरिपन घर के आंगन या जमीन पर बनाया जाता रहा है. जमीन को साफ करके कई जगह गोबर और मिट्टी से लीपा जाता है. इसके बाद चावल को पीसकर तैयार किए गए घोल से रेखाएं और आकृतियां बनाई जाती हैं. अरिपन बनाने की यह परंपरा आज भी कई जगहों पर देखने को मिलती है.यह कला समय के साथ अरिपन जमीन से निकलकर कागज तक पहुंच गया है.

कलाकार अब इसकी आकृतियों को कागज पर भी तैयार करते हैं, जिससे इस

बिहार



साथ सड़क पार कर रहे थे. इसी दौरान चारों तेज पानी की धारा में बहने लगे. युवकों की डूबता देख ग्रामीणों ने तत्परता दिखायी और दो युवकों को बचा लिया. हालांकि सत्यम और अनिल तेज बहाव में बह गये.

घटना की सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तलाश अभियान चलाकर दोनों युवकों के शव बरामद किये. हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में चीख-पुकार मच गयी.

उधर, मकेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पांच लोगों के लापता होने की सूचना है. बाढ़ का पानी लगातार निचले इलाकों में फैल रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है. बचाव दल लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं.



ज्यामितीय आकृतियों के साथ धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल भी किया जाता है.

अरिपन में बनाए जाने वाले प्रतीक भी अवसर के अनुसार बदलते हैं. इनमें कमल, शंख, स्वस्तिक, सूर्य-चंद्रमा, देवी-देवताओं से जुड़े चिह्न, पेड़-पौधे और दूसरी आकृतियां शामिल हो सकती हैं. इनका संबंध उस पूजा, व्रत या संस्कार से होता है जिसके लिए अरिपन बनाया जाता है.

अरिपन में सफेद रंग के लिए चावल को पीसकर तैयार किया गया घोल इस्तेमाल किया जाता है. कई पारंपरिक अरिपन में लाल रंग के लिए सिंदूर का भी इस्तेमाल होता है. इस तरह सफेद और लाल रंग से जमीन या कागज पर अलग-अलग आकृतियां बनाई जाती हैं.

अरिपन केवल घर की सजावट का हिस्सा नहीं है, बल्कि मिथिला की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी लोककला है. इसे बनाने की जानकारी लंबे समय से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही है. आज भी पर्व-त्योहार और शुभ अवसरों पर मिथिला के कई परिवारों में अरिपन बनाने की परंपरा जारी है.

बिहार से दिल्ली, यूपी और पूर्वोत्तर के लिए चलेंगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, बरौनी-हाजीपुर समेत कई स्टेशनों पर ठहराव

पटना, एजेंसी। आगामी पर्व-त्योहारों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल की ओर से कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जायेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से नई दिल्ली, आनंद विहार, जोगबनी, सुपौल और कामाख्या सहित कई प्रमुख शहरों के बीच विशेष ट्रेनों का परिचालन होगा। इन ट्रेनों का ठहराव बरौनी, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, शाहपुर पटोरी, खगड़िया, बेगूसराय, कटिहार समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर दिया गया है।

पूर्व मध्य रेल हाजीपुर मुख्यालय के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि पर्व-त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन स्पेशल ट्रेनों का परिचालन निर्धारित अवधि में किया जायेगा।

गाड़ी संख्या 06021/06022 पोतनूर-बरौनी-पोतनूर स्पेशल ट्रेन का परिचालन हाजीपुर, पाटलिपुत्र, डीडीयू, जबलपुर, नागपुर, विजयवाड़ा, पेरम्बूर और काटपाडी के रास्ते किया जायेगा। गाड़ी संख्या 06021 पोतनूर-बरौनी स्पेशल 4 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक प्रत्येक रविवार को पोतनूर से सुबह 6:15 बजे खुलेगी। ट्रेन मंगलवार को डीडीयू में 5:13 बजे, बक्सर में 6:13 बजे, आरा में 7:15:5 बजे, दानापुर में 8:14:5 बजे, पाटलिपुत्र में 9:130 बजे, सोनपुर में 10:11:3 बजे, हाजीपुर में 10:12:5 बजे और शाहपुर पटोरी में 11:130 बजे रुकते हुए दोपहर 1:30 बजे बरौनी पहुंचेगी।

सीवान में राजस्व अमीनों ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध, छह अक्टूबर से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश की चेतावनी

सीवान, एजेंसी। बिहार राजस्व अमीन संघ के आह्वान पर छह सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को दरौदा प्रखंड के राजस्व अमीनों ने काला बिल्ला लगाकर कार्य किया. राजस्व अमीन शैलेश यादव, अभिषेक कुमार सहित अन्य अमीनों ने काला बिल्ला लगाकर संघ की मांगों के समर्थन में विरोध जताया. अमीनों ने कहा कि उनकी लंबित मांगों पर सरकार की ओर से जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन की ओर तेज किया जाएगा.

संघ की ओर से मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की गयी है. आंदोलन के तहत एक अक्टूबर को राजस्व अमीनों ने काला बिल्ला लगाकर कार्यालय में अपने कार्यों का निषादन किया. अमीनों ने विरोध के माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी लंबित मांगों की ओर आकृष्ट कराया और शीघ्र समाधान की मांग की. संघ के आंदोलन के अगले चरण में पांच अक्टूबर को जिला



मुख्यालय पर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया जाएगा.

अमीनों का कहना है कि लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान के लिए संघ की ओर से लगातार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है. इसके बावजूद यदि मांगों के समाधान की दिशा में पहल नहीं हुई, तो आंदोलन को अगले चरण में ले जाया जाएगा. अमीनों ने स्पष्ट किया कि पांच अक्टूबर के धरना-प्रदर्शन के बाद भी यदि सरकार की ओर से मांगों पर

सकारात्मक पहल नहीं की गयी, तो छह अक्टूबर से सभी राजस्व अमीन अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे. संघ ने सरकार से आंदोलन की स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही मांगों का समाधान करने की अपील की है. राजस्व अमीन संघ की छह प्रमुख मांगों में पदोन्नति, वेतनमान एवं अन्य भत्तों में वृद्धि, नजदीकी जिले में स्थानांतरण, सेवा शर्तों को सुदृढ़ करना, कार्य के अनुरूप आवश्यक संसाधन एवं तकनीकी सहयोग

उपलब्ध कराना तथा लंबित मांगों का शीघ्र निष्पादन शामिल है. अमीनों का कहना है कि इन मांगों के समाधान से विभागीय कार्यों के निष्पादन में भी सुविधा होगी. राजस्व अमीनों ने कहा कि राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों में उनकी अहम भूमिका है. जमीन की मापी, सीमांकन सहित राजस्व से जुड़े विभिन्न कार्यों के निष्पादन की जिम्मेदारी अमीनों पर होती है. इसके बावजूद उनकी कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं.

छपरा में इस बार दशहरा पर सलेमपुर चौक का ‘स्वर्ग लोक’ पंडाल बनेगा खास आकर्षण, 55 फीट ऊंचा होगा पंडाल



55 फीट ऊंचे और 40 फीट चौड़े पंडाल के निर्माण में अभी लगभग 10 दिन का समय और लगेगा. इसके निर्माण में करीब 3000 मीटर कपड़े के साथ 600 बांस और 600 लकड़ी बीट का इस्तेमाल किया जा रहा है. पंडाल निर्माण पर करीब 11 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है.

पंडाल में कपड़े की चुनट की विशेष कारीगरी

की जा रही है. इसके साथ थर्मोकोल और कृत्रिम फूलों से भी सजावट की जायेगी. कलाकार विकास कुमार इस सजावटी कार्य को पूरा कर रहे हैं. पंडाल के सभी गुंबदों पर त्रिशूल लगाये जायेंगे. आयोजकों के अनुसार गोल्डन रंग की कृत्रिम लाइटिंग से कपड़े की चुनट और पंडाल की आकृति को और आकर्षक रूप दिया जायेगा. पंडाल के साथ मां

भवानी की भव्य प्रतिमा का निर्माण भी जारी है. पूजा समिति के अध्यक्ष लाल बाबू उर्फ लोहा सिंह, पप्पू कुमार और आदित्य कुमार ने बताया कि प्रतिमा का निर्माण कोलकाता के कलाकार नृपण दादा की देखरेख में हो रहा है. मां भवानी को शेर पर, मां सरस्वती को हंस पर, मां लक्ष्मी को उल्लू पर और सिद्धिविनायक गणेश को चूहे पर सवार दिखाया जायेगा. प्रतिमा निर्माण में पर्यावरण और प्रदूषण का ध्यान रखते हुए प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है. समिति के अनुसार प्रतिमा को भव्य स्वरूप देने के साथ पर्यावरण अनुकूल सामग्री के उपयोग पर भी जोर दिया गया है. आयोजकों के अनुसार स्वर्ग लोक की थीम को प्रभावी बनाने के लिए नई दिल्ली से लाइटिंग और साउंड सिस्टम मंगाया जा रहा है. पंडाल को गोल्डन लुक देने के लिए आधुनिक लाइटिंग का इस्तेमाल होगा. करीब आधा किलोमीटर तक झालर और कृत्रिम लाइट लगायी जायेगी.

संक्षिप्त समाचार

शिक्षकों का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है: राज्यपाल

लखनऊ, एजेंसी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शिक्षकों से कहा कि शिक्षक का कार्य केवल छात्रों को पढ़ाना नहीं है, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम करना भी है। बच्चों को अच्छ, स्वच्छ, स्वस्थ, अनुशासित और संवेदनशील नागरिक बनाने की जिम्मेदारी भी विद्यालय और शिक्षकों की है। वे बृहस्पतिवार को जनभवन स्थित



आदर्श माध्यमिक विद्यालय के छात्रों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व पर आधारित भाषण कार्यक्रम के बाद बच्चों को संबोधित कर रही थीं। राज्यपाल ने कहा कि कक्षा-10 के छात्रों का परिणाम शत-प्रतिशत आना चाहिए। कमजोर छात्रों को चिह्नित कर उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं व विशेष शिक्षण किया जाए। उन्होंने विद्यालय में छात्रों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने को कहा। शिक्षक छात्रों के होमवर्क की नियमित जांच करें। छात्रों से राज्यपाल ने कहा कि यह उम्र परिश्रम और मेहनत करने का समय है। महात्मा गांधी ने भी साधारण परिवेश से आगे बढ़कर अपने दृढ़ संकल्प, अनुशासन और निरंतर परिश्रम से देश और दुनिया को दिशा दी। इस अवसर पर महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुछाहार मंत्री बेबी रानी मौर्या, विशेष कार्याधिकारी राज्यपाल डॉ. सुधिर महादेव बोबडे आदि उपस्थित थे।

नदियों में डाली जाएंगी 2.75 लाख चितला मछली की अंगुलिकाएं

गोरखपुर , एजेंसी। प्रदेश की राज्य मछली चितला के संरक्षण और संवर्धन के लिए मत्स्य विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। विभाग की ओर से मंडल की प्रमुख नदियों में चितला के 2.75 लाख बच्चे (मत्स्य अंगुलिकाएं) डाले जाएंगे। इसके लिए करीब तीन इंच आकार के चितला के बच्चे कोलकाता से मंगाए जा रहे हैं। विभाग के अनुसार बड़े आकार के बच्चे नदी में छोड़ने से दूसरी मछलियों का आहार बनने की आशंका कम रहती है। इससे उनके जीवित रहने की संभावना भी बढ़ जाती है। चितला की संख्या लगातार कम होने के कारण विभाग ने इसके संरक्षण पर जोर दिया है। उपनिदेशक मत्स्य बृजेश कुमार ने बताया कि चितला के संरक्षण के साथ नदियों में मछली उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। गोरखपुर की राप्ती नदी में 75 हजार और सरयू नदी में 50 हजार चितला के बच्चे डाले जाएंगे। कुशीनगर की गंडक नदी में 50 हजार तथा महाराजगंज, देवरिया की नदियों में 50-50 हजार बच्चे छोड़े जाएंगे। प्रदेश की अन्य नदियों में भी रीवर रेचिंग की जाएगी।

प्रो. प्रदीप दीक्षित कोमिला अंतरराष्ट्रीय संस्कृत रत्न सम्मान

कानपुर , एजेंसी। वीएसएसडी कॉलेज के प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित को थाईलैंड के बैंकॉक स्थित शिल्पकॉर्न विश्वविद्यालय में आयोजित अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल संस्कृत संगोष्ठी में अंतरराष्ट्रीय संस्कृत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत सरकार की ओर से संचालित संस्कृत अध्ययन केंद्र और ग्लोबल संस्कृत फोरम के संयुक्त तत्वावधान में हुई संगोष्ठी में देश-विदेश के विद्वानों ने भाग लिया। इसमें 300 से अधिक शोधपत्र प्रस्तुत किए गए।

कार्यक्रम में भारत के राजदूत पुनीत अग्रवाल और अंतरराष्ट्रीय सचिव डॉ. राजेश मिश्रा अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रो. दीक्षित को संस्कृत भाषा एवं साहित्य के संरक्षण, प्रचार-प्रसार, संवर्धन और उन्नयन के क्षेत्र में उनके दीर्घकालीन एवं समर्पित योगदान के लिए सम्मानित किया गया। संगोष्ठी में प्रो. दीक्षित और डॉ. अनुराग दीक्षित की पुस्तकों ज्योतिष वैखरी और ज्योतिष प्रबोधिनी का विमोचन भी हुआ। शिक्षाविदों और संस्कृत प्रेमियों ने उन्हें बधाई दी।

पीडीए की एकजुटता ही सत्ता परिवर्तन का आधार: देवेश शाक्य

अलीगढ़ , एजेंसी। एटा से सपा सांसद देवेश शाक्य ने कहा है कि पीडीए की एकजुटता ही सत्ता परिवर्तन का आधार बनेगी। वे बृहस्पतिवार को जेल रोड स्थित पूर्व विधायक जफर आलम के कैप कार्यालय पर पीडीए संवाद कर रहे थे।



विधायक जफर आलम ने कहा कि सपा ने सदैव सभी वर्गों को साथ लेकर विकास की राजनीति की है। लोग भाजपा की जनविरोधी नीतियों से परेशान हैं। हमें बुथ स्तर तक संगठन को मजबूत करते हुए सपा के विकास कार्यों को घर-घर पहुंचाना होगा। महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी ने कहा कि कार्यकर्ता निष्ठा से मैदान में उतरें। जिला महासचिव मनोज यादव ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनार, जस्सू शेरवानी, विनोद सविता, ख्वाजा जिन्नान, अमिर आबिद मौजूद रहे।

अलीगढ़, एजेंसी। एक कचौड़ी, दो समोसा... इस वीसी का क्या भरोसा। एक जीरा, दो अजवाइन... मर्द जात दो रिजाइन। आलू लो, पूरी लो... इन मर्दों से दूरी लो। ये किसी रसोई का मेन्यू नहीं बल्कि जेन-जी युवतियों के विरोध की आवाज है।

जिस किचन तक महिलाओं को सीमित किए जाने की बातें लंबे समय तक होती रही, उसी किचन के सामान और रोजमर्रा की भाषा को अब लड़कियां सड़क पर विरोध का हथियार बना रही हैं। दिल्ली के जंतर-मंतर, पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) से लेकर एएमयू तक छात्राओं के प्रदर्शनों में विरोध के तरीके और भाषा में यह बदलाव दिखाई दे रहा है।

लंबे भाषणों और पारंपरिक नारों के साथ अब मीम, तुकबंदी, व्यंग्य और रोजमर्रा के खान-पान से जुड़े शब्द भी विरोध का हिस्सा बन रहे हैं। इन नारों का

100 में बीएचयू के विशेषज्ञ बताएंगे मुहूर्त, 250 रुपये में कर्मकांड का परामर्श

वाराणसी, एजेंसी। बीएचयू में पहली बार ज्योतिष ओपीडी को अस्पताल की तर्ज पर 8 विषयों में स्पेशलाइज्ड कर दिया गया है। जन्म कुंडली, मुहूर्त तिथि, विवाह-मेलापक, वास्तु के आधार पर जमीन का नक्शा बनाने, मिट्टी में सुधार, रत्नधारण



और कर्मकांड कराने वाले लोगों को बांटकर ज्योतिषी परामर्श और समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

मुहूर्त निकलवाने के लिए 100 रुपये, कर्मकांड परामर्श के लिए 250 रुपये, प्रोफेसर ज्योतिषाचार्य को जिले से बाहर ले जाने पर 21 हजार और जिले में 11 हजार रुपये चुकाने होंगे। वाहन खर्च अलग से देना होगा। इसमें 50 प्रतिशत दक्षिणा भी शामिल है।

इससे पहले बीएचयू में सिर्फ कुंडली देखने-बनाने की ही सुविधा थी, जो 16



मकसद सिर्फ ध्यान खींचना नहीं, बल्कि महिला सुरक्षा, स्वतंत्रता, बराबरी और अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद लेने के अधिकार की बात को ज्यादा सहज और

किचन से निकला विरोध का नया मेन्यू



यादगार तरीके से सामने रखना है।

एएमयू की बीए ऑनर्स की छात्रा सुमैया और इबा नूर कहती हैं कि महिलाओं पर लंबे समय से यह ठप्पा लगाया जाता रहा है

पुरुषों पर नहीं, सोच पर सवाल

छात्रा महबीश कहती हैं कि इन नारों का मकसद सभी पुरुषों को निशाना बनाना नहीं है। सभी पुरुष एक जैसे नहीं हैं, लेकिन कुछ के व्यवहार की वजह से पूरे पुरुष समाज पर सवाल उठते हैं। पुरुषों को यह समझना होगा कि महिलाओं को भी अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। संविधान महिलाओं को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देता है।

कि उनकी दुनिया किचन तक सीमित है। अब उसी किचन की रेंसिपी और रोजमर्रा की चीजें विरोध की आवाज बनकर सड़क पर उतर रही हैं।

संतान की दीर्घायु को महिलाएं रखेंगी निर्जला व्रत, 16 गांठों के रक्षा सूत्र का है महत्व; खास अनुष्ठान

वाराणसी, एजेंसी। काशी में संतान के दीर्घायु जीवन, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना के साथ महिलाएं जीवित्युत्रिका (जितितिया) का व्रत रखेंगी। इसके साथ ही लक्ष्मा स्थित प्राचीन लक्ष्मी कुंड पर चल रहे 16 दिवसीय पारंपरिक सोरहिया मेले का शनिवार को विधिवत समापन होगा।

बृहस्पतिवार को मां लक्ष्मी के दर्शन के लिए महिलाओं की लाइन लगी रही। जीवित्युत्रिका व्रत को लेकर काशी के प्रमुख गंगा घाटों, अरस्सी, दशाश्वमेध, पंचगंगा, ईश्वरगंगी, बरेका सूर्य सरोवा सहित विभिन्न कुंडों व सरोवरों पर आस्था का सैलाब उमड़ेगा। माताएं 24 घंटे का निर्जला उपवास रखकर जीमूतवाहन की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करेंगी। व्रती महिलाएं सुबह पवित्र नदियों व सरोवरों में स्नान कर संतान रक्षा का संकल्प लेंगी और कथा श्रवण के उपरांत बांस की ठोकरी में टेकुआ, फल और अक्षत अर्पित करेंगी।

दूसरी ओर, सोरहिया मेले के अंतिम दिन लक्ष्मा स्थित महालक्ष्मी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। यहां 16 दिनों तक कठोर अनुष्ठान करने वाली महिलाएं 16 गांठ वाले पवित्र रक्षा सूत्र (सोरहिया डोरा) का पूजन कर व्रत का उद्घापन करेंगी। देवी को 16 प्रकार के मौसमी फल, मिष्ठान और सुह्रग सामग्री अर्पित की जाएगी। मंदिर के महंत शिवप्रसाद पांडेय उर्फ लिंगिया महाराज ने बताया कि सोरहिया मेले के अंतिम दिन व्रती महिलाओं की भीड़ उमड़ेगी। महिलाएं मां लक्ष्मी के दर्शन कर संतान सुख की कामना करेंगी।

मैडिकल कॉलेज में एमआरआई मशीन का पाइप फटा, हीलियम गैस लीक; एक महीने तक जांच ठप रहने की आशंका



एमआरआई मशीन करीब 10 साल पुरानी है। मशीन में लगे सुपरकंडक्टरिंग मैग्नेट को सुरक्षित तापमान पर बनाए रखने के लिए उसे लगातार ठंडा रखना जरूरी होता है। इसके लिए तरल हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। पिछले कुछ दिनों से मशीन के भाग पड़ना में हल्की लीकेज की समस्या सामने आ रही थी। बृहस्पतिवार को पाइप फटने के बाद हीलियम गैस तेजी से बाहर

निकल गई और मशीन बंद हो गई।

इसके बाद एमआरआई जांच की सुविधा पूरी तरह ठप हो गई।

गरीब और गंभीर मरीजों पर पड़ेगा ज्यादा असर- मैडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में मेरठ और आसपास के जिलों से मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। इनमें गरीब और गंभीर मरीज भी शामिल होते हैं। एमआरआई सेवा बंद रहने के कारण इन मरीजों को अब जांच के लिए

दूसरे सरकारी अस्पतालों का रुख करना पड़ सकता है।

वहीं, जिन मरीजों को सरकारी स्तर पर जांच की सुविधा नहीं मिल पाएगी, उन्हें निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों में एमआरआई करानी पड़ सकती है। निजी केंद्रों पर जांच कराने में मरीजों को अधिक खर्च उठाना पड़ेगा। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि एमआरआई सेवा को जल्द से जल्द बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मरम्मत और हीलियम गैस की व्यवस्था में लगेगा एक महीना- मैडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आर.सी. गुप्ता ने बताया कि मशीन को दोबारा शुरू करने के लिए हीलियम गैस की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही मशीन की तकनीकी मरम्मत और उसे सुरक्षित तरीके से दोबारा चालू करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसमें कम से कम एक महीने का समय लग सकता है।

त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में निकलेगी राम बरात

आगरा, एजेंसी। प्रभु श्रीराम की बरात 6 अक्तूबर को त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में निकाली जाएगी। मन:कामेश्वर से जनकपुरी तक के रूट को चार सुपर जोन और 8 जोन में बांटा गया है। हर जोन के प्रभारी एडीसीपी और एसीपी को बनाया गया है। जिस रास्ते से बरात निकलेगी, वहां पर घरों की छतों पर पुलिस फोर्स रहेगी। पुलिस के 1500 सिपाहियों के साथ पीएस की 1000 से अधिक जवान रहेंगे। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि राम बरात और जनकपुरी आयोजन के लिए सुरक्षा का खाका खींचा गया है। पुराने शहर से राम बरात की शुरूआत होती है। यह अलग-अलग क्षेत्र में घूमती है। बाद में जनकपुरी पहुंचती है। सुपर जोन प्रभारी एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी रहेंगे जबकि जोन का प्रभारी एसीपी स्तर के अधिकारी को बनाया गया है। 10 से 12 झांकियों को एक एसीपी, एक इस्पेक्टर और 20 से अधिक एसआई और सिपाहियों की मौजूदगी में निकाला जाएगा। इसके अलावा श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के स्वरूप की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

बैंड संचालकों के साथ बैठक

पुलिस लाइन में बृहस्पतिवार को बैंड संचालकों के साथ पुलिस अधिकारियों ने बैठक की। डीसीपी सिटी ने बताया कि राम बरात में शामिल बैंड के 50 से अधिक कर्मचारी होते हैं। इनके अलावा उनकी गाड़ी भी होती है। कई बार गाड़ी बड़ी होने के कारण घंटिया आजम खां से फुलट्टी की तरफ जाने वाले मार्ग पर फंस जाती हैं। इससे आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। संचालकों से कहा गया कि वह ऐसी गाड़ी लेकर आए जो संकरे रास्ते से आसानी से निकल सके।



नगर पालिका के ईओ डीके राय ने बताया कि अभी तक वार्ड के किसी व्यक्ति ने इस समस्या की शिकायत नहीं की है। जानकारी लेने के बाद मामला सही मिलने पर जल्द निस्तारण कराया जाएगा। मोहल्ले में ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव कराया जाएगा।

नाले की सफाई नहीं होने से गंदगी और पानी सड़क पर जमा है। सफाई के दौरान निकाला गया कचरा भी सड़क किनारे छोड़ दिया जाता है, जिससे कई दिनों तक दुर्गंध उठती रहती है। इस माहौल में रहना मुश्किल हो गया है।

- **विवेक कुमार मिश्रा**, रायगंज। करीब दो महीने से पानी जमा है और अब घरों में भी गंदा पानी पहुंच रहा है। बच्चों को स्कूल जाने और परीक्षा देने में परेशानी हो रही है। प्रशासन को जल्द जलनिकासी की व्यवस्था करनी चाहिए।

- **नागेश कुमार मिश्रा**, रायगंज। जलभराव और कीचड़ के कारण सड़क पर चलना मुश्किल है। आए दिन बच्चे और बुजुर्ग फिसलकर गिर रहे हैं। समस्या लंबे समय से बनी है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ

- **श्वेता श्रीवास्तव**, रजदेपुर।



गिर रहे हैं। बच्चे और बुजुर्ग भी चोटिल हो रहे हैं। समस्या लंबे समय से बनी होने के बावजूद जिम्मेदारों की ओर से अब तक ठोस समाधान नहीं किया गया है।

रजदेपुर में अतिक्रमण से बाधित है पानी की निकासी- वार्ड नंबर 11 के सभासद कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 में तत्कालीन जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने रौजा की जलभराव की समस्या खत्म करने के लिए रेलवे क्रासिंग के पास नाला खोल दिया था।

संपादकीय

बिजली बिल में बकाया ट्रेफिक चालान राशि

सड़क पर यातायात नियम तोड़कर चालान कटवाना आसान है, लेकिन अब उसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लंबित ई-चालानों की वसूली के लिए ऐसा तंत्र बनाने की जरूरत बताई है, जिससे नियम तोड़ने वालों को जुर्माना चुकाने के लिए मजबूर होना पड़े। अदालत ने यहां तक सुझाव दिया कि बकाया यातायात चालान को बिजली बिल से जोड़ दिया जाए। बिजली का बिल नहीं चुकाने पर जिस तरह बिजली काटने की कार्रवाई होती है, उसी तरह चालान की वसूली सुनिश्चित करने का रास्ता खोजने की बात अदालत ने कही।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने साफ कहा कि केवल हजारों-लाखों ई-चालान काटते रहना पर्याप्त नहीं है। असली सवाल जुर्माने की वसूली का है।

अदालत के सामने रखे आंकड़ों के मुताबिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में करीब 45 हजार करोड़ रुपये के ई-चालान जारी किए गए हैं, जिनमें लगभग 25 हजार करोड़ रुपये ही वसूल हो पाए हैं। यानी करीब 20 हजार करोड़ रुपये अब भी बकाया हैं।

यह सुनवाई 2012 से लंबित सड़क सुरक्षा से जुड़ी जनहित याचिका के तहत हुई। अदालत ने लंबित चालानों से निपटने के लिए कई कठोर विकल्पों पर भी विचार किया। बकाया चालान वाले वाहनों को काली सूची में डालने, वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण रोकने और पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण पर रोक जैसे उपायों की चर्चा हुई। यहां तक कि ऐसे वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र और फिटनेस प्रमाणपत्र रोकने तथा चालक के लाइसेंस के नवीनीकरण पर भी



कार्रवाई का सुझाव सामने आया।

अदालत ने परिवहन संबंधी ऑनलाइन व्यवस्था पर ऐसे वाहनों को चिह्नित करने और

बकाया चालान साफ होने तक स्वामित्व परिवर्तन रोकने की बात कही। इसके साथ ही सड़कों पर रैंडम चेक बढ़ाने का सुझाव भी दिया गया, ताकि

पता चल सके कि किन वाहनों पर पुराने ई-चालान लंबित हैं। हम आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के आंकड़े इस समस्या की गंभीरता को और ज्यादा उजागर करते हैं। 28 सितंबर 2026 तक दिल्ली में यातायात चालानों और कैमरे से जारी कोटिडों की कुल लंबित दर करीब 73 प्रतिशत है। मौके पर काटे गए करीब 1.7 करोड़ चालानों में लगभग 1.1 करोड़ लंबित हैं, जबकि कैमरे से जारी करीब 4.5 करोड़ कोटिडों में लगभग 3.4 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ है। कैमरा आधारित कोटिडों की लंबित दर करीब 75.8 प्रतिशत, जबकि मौके पर काटे गए चालानों की लंबित दर करीब 66.4 प्रतिशत है। बकाया चालानों में सबसे ऊपर तेज रफ्तार हैं, जिसके करीब 1.7 करोड़ चालान लंबित हैं। इसके बाद गलत पार्किंग के करीब 85.4 लाख, बिना हेलमेट करीब 47.8

लाख और लालबत्ती तोड़ने के करीब 47.5 लाख मामले हैं। इस साल 28 सितंबर तक भी तेज रफ्तार के करीब 18.5 लाख, गलत पार्किंग के 17.3 लाख और बिना हेलमेट के 11.2 लाख चालान दर्ज हुए हैं। वसूली की राह में भुगतान प्रक्रिया भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। कई लोग लोक अदालतों का इंतजार करते हैं। कुछ मामलों में 2,000 रुपये का चालान लोक अदालत में 200 रुपये में निपटने की संभावना बताई जाती है। दूसरी ओर, रोज नए चालान बनते हैं, जबकि लोक अदालतें निश्चित समय पर लगती हैं, जिससे लंबित मामलों का ढेर बढ़ता रहता है। वहीं तेज रफ्तार के मामलों में ऑनलाइन भुगतान की समयसीमा 90 दिन है, जबकि लालबत्ती उल्लंघन में शिकायत दर्ज कराने के लिए 15 दिन की अवधि होती है।

छात्रों में बढ़ती आक्रामकता, समाधान जरूरी

डॉ. वरिन्द्र भाटिया

पंजाब के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में छात्रों का आक्रोशित होकर आक्रामक प्रदर्शन, उच्च शिक्षा जगत के लिए चिंताएं पैदा कर रहा है। चिंता का बड़ा कारण इसलिए भी है क्योंकि जिस उम्र में छात्रों के मानसिक और सामाजिक विकास की नींव रखी जाती है, उसी उम्र में कई छात्रों में आक्रामकता पर करने लगी है। भारत के छात्रों में आक्रामक मानसिकता का पनपना हमारी शिक्षा, पारिवारिक एवं सामाजिक संरचना पर कई सवाल खड़े करता है। यह रुझान छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर तो नकारात्मक प्रभाव डाल ही रहा है, इसे भविष्य में समाज में अस्थिरता के लिए बड़ा खतरा भी मानना चाहिए। बड़ा सवाल है कि जिन वजहों से छात्रों के भीतर आक्रामकता पैदा हो रही है, उनसे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? यूं तो उम्र के इस पड़ाव पर उनको सही राह दिखाने की जिम्मेदारी परिजन और शिक्षक और शैक्षणिक प्रशासन की ही होती है। आज दोनों ही कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से शायद नहीं निभा पा रहे हैं, इसके लिए सभी समाजसेवियों, शिक्षाविदों और चिंतकों को आगे आना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो, छात्रों में आक्रामकता कुटुंब और दबाव का नतीजा है। छात्रों में गुस्सा, निराशा या चिंता जैसी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता का अभाव होता है, जिससे वे आक्रामक हो जाते हैं। पढ़ाई और परीक्षा में अच्छे अंक लाने का भारी दबाव और असफलता का डर छात्रों में चिड़चिड़ापन और आक्रामकता पैदा करता है। ध्यान की कमी और अतिसक्रियता के कारण छात्र तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर एक ऐसा विकार है, जिसमें नियमों को तोड़ना और आक्रामक व्यवहार करना शामिल होता है। इसमें छात्र बड़ों और शिक्षकों के प्रति लगातार अवज्ञाकारी और गुस्सेलत रुख अपनाते हैं। लंबे समय तक रहने वाली उदासी या आंतरिक मानसिक पीड़ा भी गुस्से के रूप में बाहर आती है। बचपन में किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण, घर में हिंसा देखना, या उपेक्षा का शिकार होना छात्रों के मन में गहरे डर और गुस्से को जन्म देता है। जब छात्र अपनी बात या अपनी जरूरतें दूसरों को सही तरीके से नहीं समझा पाते, तो उनकी झुंझलाहट आक्रामकता में बदल जाती है। जो छात्र खुद स्कूल या दोस्तों के बीच रैगिंग या उत्पीड़न का शिकार होते हैं, वे अवसर अपनी संकुचन या बदले की भावना को दूसरों पर आक्रामकता के जरिए निकालते हैं। खुद को अकेला महसूस करना या कम आत्मसम्मान होना भी छात्रों में कुटुंब और आक्रामक प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। इन मनोवैज्ञानिक कारणों का निदान कैसे होगा? कैम्पस का माहौल यदि सकारात्मक नहीं हो तो भी छात्र आक्रामक हो जाते हैं। क्या देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में मनोवैज्ञानिक सलाहकारों की व्यवस्था है? क्या इस दिशा में में रेगुलैटरी अथॉरिटी की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? क्या उच्च शिक्षा संस्थानों का धीरे-धीरे, व्यापारिक संस्थानों में तबदील हो जाना, शिक्षा जगत के सामाजिक-सार्वजनिक हितों की रक्षा कर सकेगा? ऐसे कई सवाल हैं, जिनका हल करने से छात्रों में आक्रामकता को कम किया जा सकता है।

आज का कार्टून



एआई से जुड़े महाविनाश के खतरे: नियंत्रित कमान जरूरी

ललित गर्ग

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आज मानव सभ्यता की सबसे प्रभावशाली तकनीकी उपलब्धियों में शामिल है। चिकित्सा, शिक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान, कृषि, उद्योग और प्रशासन से लेकर रोजमर्रा के जीवन तक इसके उपयोग ने विकास की गति को अमूर्तपूर्ण बनाया है। लेकिन जितनी तेजी से एआई की क्षमताएं बढ़ रही हैं, उतनी ही गंभीरता से उसके दुरुपयोग और नियंत्रण से बाहर जाने के जोखिमों पर भी विचार करना होगा। सितंबर 2026 में संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल ने भी चेताया है कि एआई की क्षमताओं की गति के मुकाबले उसके सुरक्षित उपयोग के नियम पीछे छूट रहे हैं और अधिक स्वायत्त एआई एजेंटों के रखना एक वास्तविक चुनौती बन रहा है।

माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स की हालिया चेतावनी विशेष महत्व रखती है। उन्होंने कहा है कि एआई गलत हथों में पड़ने पर अत्यंत व्यापक जनहानि का माध्यम बन सकता है और सरकारों को इसके लिए प्रभावी नियमन की दिशा में काम करना चाहिए। गेट्स की चिंता केवल भविष्य की किसी काल्पनिक आशंका पर आधारित नहीं है, एआई के दुरुपयोग के कुछ ठोस उदाहरण सामने आने लगे हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बदलाव एआई एजेंट्स के रूप में दिखाई दे रहा है। पारंपरिक एआई मुख्यतः प्रश्नों के उत्तर देता था, लेकिन एजेंट इंटरनेट पर जा सकता है, वेबसाइट खोल सकता है, कोड लिख सकता है, सूचनाएं खोज सकता है और निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए अनेक चरणों में स्वयं कार्रवाई कर सकता है।

यही क्षमता उपयोगी होने के साथ जोखिमपूर्ण भी है। सितंबर 2026 में संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिक पैनल ने ओपेनएआई से संबंधित एक घटना का उल्लेख किया, जिसमें परीक्षण के दौरान एआई एजेंट्स ने नेटवर्क प्रतिबंधों को पार किया, अलग-अलग प्रक्रियाओं के बीच संपर्क किया और ओपेनएआई तथा हुगिंग फेस की प्रणालियों के कुछ हिस्सों से समझौता किया। स्वतंत्र संस्था एमईटीआर की जांच के अनुसार इस घटना में लगभग 1,200 एजेंट्स ने 70,000 से अधिक संदेश और फाइलें साझा कीं तथा लगभग 700 एजेंट्स हुगिंग फेस पर हुए हमले में शामिल हुए। यहां सावधानी जरूरी है। इन घटनाओं को यह प्रमाण मान लेना कि एआई निश्चित रूप से मानव नियंत्रण से बाहर हो गया है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। ये नियंत्रित परीक्षण और सुरक्षा-मूल्यांकन के दौरान सामने आई घटनाएं थीं। लेकिन इनका महत्व इस बात में है कि अधिक सक्षम एजेंट जब जटिल लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वे उन रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी कल्पना उनके निर्माताओं ने नहीं की थी। स्वयं ओपेनएआई ने भी एजेंट्स के इंटरनेट उपयोग, बाहरी सामग्री से होने वाले 'प्रॉम्प्ट इंजेक्शन' और डेटा चोरी जैसे जोखिमों को लेकर सुरक्षा उपायों की जरूरत स्वीकार की है।

एआई के सैन्य दुरुपयोग की आशंका भी अब केवल सैद्धांतिक नहीं रह गई है। सितंबर 2026 में एंथ्रोपिक ने बताया कि यमन में हूती-नियंत्रित क्षेत्र से जुड़े लोगों ने उसके क्लाउड एआई का इस्तेमाल निर्देशित रॉकेट और मिसाइलों के मार्गदर्शन, नियंत्रण और नेविगेशन से जुड़े सॉफ्टवेयर विकसित करने के प्रयास में किया। कंपनी के अनुसार सुरक्षा उपायों ने अनेक अनुरोधों को रोका, लेकिन उपयोगकर्ताओं ने अपनी मंशा छिपाकर और काम को अलग-अलग सत्रों में बांटकर कुछ सुरक्षा अवरोधों को पार करने की कोशिश की। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार हथियार-विकास का प्रयास सफल नहीं हुआ, हालांकि एक निर्देशित रॉकेट का परीक्षण विफल हुआ और उसके बाद एआई से उसकी समस्या समझने का प्रयास किया गया। यही वह बिंदु है जहां एआई और

गलत सूचना फैलाने में एआई का इस्तेमाल संभव है। संयुक्त राष्ट्र के आकलन में भी साइबर हमलों, वित्तीय धोखाधड़ियां, सोशल इंजीनियरिंग और डीपफेक को एआई से जुड़े प्रमुख जोखिमों में गिना गया है। आज यदि किसी व्यक्ति की आवाज की हूबहू नकल करके उसके परिजन से पैसे मागे जा सकते हैं, किसी अधिकारी या संस्था का नकली वीडियो बनाया जा सकता है अथवा बड़े पैमाने पर स्वचालित साइबर हमले किए जा सकते हैं, तो डिजिटल समाज में विश्वास की बुनियाद ही प्रभावित हो सकती है।

भारत के लिए यह चिंता और अधिक महत्वपूर्ण है। करोड़ों भारतीय बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, सरकारी सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और व्यापार के लिए डिजिटल प्रणालियों पर निर्भर हैं। इसलिए एआई-आधारित साइबर हमले का प्रभाव किसी एक कंप्यूटर या संस्था तक सीमित नहीं रह सकता। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी साइबर सुरक्षा को उपरती एआई, मशीन लर्निंग और अन्य तकनीकों के साथ जुड़ी चुनौती के रूप में रेखांकित किया है तथा सीईआरटी-इन जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है। भारत को एआई के विकास में पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन उसके साथ साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को समान गति से मजबूत करना होगा। दूसरी बड़ी चुनौती वैश्विक शक्ति-संतुलन की है। एआई पर नियंत्रण यदि कुछ देशों या कुछ बड़ी निजी कंपनियों तक सीमित हो गया, तो तकनीकी क्षमता आर्थिक और सामरिक शक्ति का नया आधार बन

सकती है। अमेरिका और चीन जैसे बड़े तकनीकी एवं सैन्य शक्तियों के बीच एआई प्रतिस्पर्धा पहले ही वैश्विक राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। इसलिए एआई का प्रश्न केवल यह नहीं है कि कौन सबसे शक्तिशाली मॉडल बनाएगा, प्रश्न यह भी है कि इन मॉडलों की सीमाएं कौन तय करेगा, उनके परीक्षण की स्वतंत्र व्यवस्था कौन करेगा और किसी गंभीर जोखिम की स्थिति में किसके पास हस्तक्षेप करने की वैध शक्ति होगी।

इसीलिए केवल कंपनियों के स्वैच्छिक आत्म-नियमन पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं लगता। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एआई के विकास को रोक देना समाधान नहीं है। यही तकनीक कैम्सर अनुसंधान, नई दवाओं, वैज्ञानिक खोजों, शिक्षा, आपदा प्रबंधन और उत्पादकता में बड़ी भूमिका निभा सकती है। स्वयं संयुक्त राष्ट्र एआई को मानव विकास के लिए

असंधारण संभावनाओं वाली तकनीक मानता है, साथ ही मजबूत सुरक्षा-व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर देता है। इसलिए दुनिया को 'एआई बंद करो' नहीं, बल्कि 'एआई को जिम्मेदारी के साथ विकसित करो' का रास्ता अपनाना होगा। वैश्विक स्तर पर न्यूनतम सुरक्षा मानक, स्वतंत्र परीक्षण, उच्च जोखिम वाले एआई सिस्टम के लिए अनिवार्य निगरानी, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मानव की अंतिम स्वीकृति, साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल, दुरुपयोग की रिपोर्टिंग और देशों के बीच सूचना-साझेदारी जैसी व्यवस्थाएं आवश्यक

हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेर्रेस ने भी जुलाई 2026 में एआई के लिए व्यापक वैश्विक नियंत्रण और सुरक्षा-केंद्रित व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया था। मानव इतिहास में विज्ञान ने मनुष्य की शक्ति बढ़ाई है, लेकिन हर बढ़ती शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ी है। परमाणु युग ने दुनिया को यह सिखाया कि अत्यधिक शक्तिशाली तकनीक को केवल उसके निर्माताओं की सदिच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता। एआई की चुनौती कुछ मायनों में अलग है-यह डिजिटल, तीव्र, व्यापक और सीमाओं के पार काम करने वाली तकनीक है। इसलिए इसकी सुरक्षा-व्यवस्था भी वैश्विक होनी चाहिए। आज आवश्यकता एआई की गति को अंधाधुंध रोकने की नहीं, बल्कि उसकी दिशा पर मानवीय नियंत्रण बनाए रखने की है। मशीन कितनी भी बुद्धिमान क्यों न हो जाए, अंतिम निर्णय का नैतिक दायित्व मनुष्य से अलग नहीं किया जा सकता। एआई मानवता का संवेक बने, उसका स्वामी नहीं, विकास का साधन बने, विनाश का हथियार नहीं-यही इस तकनीकी युग की सबसे बड़ी कसौटी है। बिल गेट्स की चेतावनी को भय फैलाने के बजाय समय रहते सावधान करने वाली घंटी के रूप में देखना चाहिए। यदि दुनिया अभी से साझा सुरक्षा मानकों और प्रभावी वैश्विक निगरानी की दिशा में आगे बढ़ती है, तो एआई की अपार शक्ति मानव कल्याण की ऊर्जा बन सकती है, लेकिन यदि सुरक्षा की चिंता को विकास की दौड़ में लगातार पीछे धकेला गया, तो यही शक्ति ऐसी समस्याएं पैदा कर सकती है जिनका समाधान बाद में करना कहीं अधिक कठिन होगा।

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की जरूरत

सैयद कामरान

कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा विकल्प यही है कि वह समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े और सीटों की मांग बढ़ा-चढ़ाकर न करे, बल्कि यथार्थवादी रखे, यानी सीमित सीटों पर ही संसाधन केंद्रित करे। कम सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करने से दो फायदे होंगे-एक तो 2029 के लिए सीट बंटवारे की बातचीत में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी और दूसरा, पार्टी को मौजूदा विधायकों का एक मजबूत समूह मिलेगा। इस तरह की जमीनी उपस्थिति केंद्रीय नेतृत्व की दृश्यता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, ऐसे में कांग्रेस के रणनीतिकारों को एक असहज सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है-मौजूदा गठबंधन में समाजवादी पार्टी (एस.पी.) की स्थिति कहीं अधिक मजबूत है। 'इंडिया गठबंधन की एकता' के दिखाने से परे, गणितीय समीकरण और संगठनात्मक क्षमता भी यही संकेत देती है- कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की जरूरत समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की जरूरत से कहीं अधिक है। पहला अंतर संरचनात्मक है। समाजवादी पार्टी कोई व्यक्ति-प्रधान संगठन नहीं है, जो कुछ समय के लिए जनसमर्थन बढ़ाकर सत्ता के पलटने पर गायब हो जाता है। इसके पास एक सक्रिय कार्यकर्ता दल और बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, तीन दशकों में निर्मित यादव-मुस्लिम सामाजिक पूंजी है, गैर-यादव अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) और दलितों का बढ़ता हुआ समर्थन है तथा एक जिला-से-गांव स्तर का ढांचा है जो खराब चुनावी दौर में भी टिका रहता है। इसकी तुलना तुर्कमूल कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से करें जो 'नेता-समर्थक' की संरचना पर आधारित हैं, नेता की लोकप्रियता के समय ये दल शक्तिशाली होते हैं लेकिन लोकप्रियता कम होने पर इनकी संरचनात्मक मजबूती खत्म हो जाती है।

कांग्रेस की राज्य इकाई उसी खामी से ग्रस्त है, जिसका समाधान सपा ने कर लिया है। यह समर्थकों पर आधारित एक खोखली इकाई है, जो मीडिया कवरेज, राहुल गांधी की छिटपुट यात्राओं और क्षणिक ऑनलाइन समर्थन पर निर्भर है तथा इसमें जमीनी स्तर पर ऐसी बुनियादी संरचना का अभाव है, जो मतदान के दिन भावनाओं को वोटों में बदल सके। इसके विपरीत, सपा का कार्यकर्ता एक स्थायी संपत्ति है, जो 2027 में चाहे कोई भी जीते, कहीं नहीं जाने वाला, यही स्थायित्व उसकी ताकत है। दूसरा तर्क, जो शायद अधिक निर्णायक है, वह है वोटों का गणित। उत्तर प्रदेश का मुकाबला अब चार-पक्षीय संघर्ष नहीं रह गया, यह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और सपा के नेतृत्व वाले विपक्ष के बीच एक द्विध्रुवीय संघर्ष में तबदील हो गया है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का वोट शेयर लगातार घट रहा है और जो थोड़ा-बहुत वोट बचा है, साथ ही जाति आधारित और क्षेत्रीय दलों में बिखरी भाजपा विरोधी भावना, उसका कोई

निश्चित ठिकाना नहीं है। यह उस गैर-भाजपा गठबंधन की ओर आकर्षित होता है, जिसके जीतने की सबसे अधिक संभावना होती है।

दो धुवों वाली चुनावी दौड़ में, 'भाजपा को छोड़कर कोई भी' का बचा हुआ वोट समान रूप से नहीं बंटता, यह उस पार्टी के पीछे एकजुट हो जाता है, जिसे असली चुनौती देने वाली पार्टी के



रूप में देखा जाता है और उत्तर प्रदेश में यह स्पष्ट रूप से सपा है, कांग्रेस नहीं। कांग्रेस, जो एक दशक से अधिक समय से उत्तर प्रदेश के अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में एकल अंकों में बनी हुई है, औसत विपक्षी मतदाता के लिए इस गणना का हिस्सा नहीं है। वोट बढ़ाने में इसकी क्षमता सीमित है, जबकि सपा की छवि सत्ता-

विरोधी वोटों को आर्जित करती है, जो सीटों का फैसला करती है। तीसरा तर्क कथार्थक स्वामित्व का है। 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव अभिलेख यादव को विपक्ष के चेहरे के रूप में और पी.डी.ए. (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) को संगठनात्मक सामाजिक गठबंधन के रूप में उभार रहे हैं। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में पी.डी.ए. की तरह कोई प्रतिस्पर्धी कथा नहीं है, उसका राष्ट्रीय न्याय का ढांचा और भारत जोड़ो से जुड़ा संदेश पी.डी.ए. की तरह उत्तर प्रदेश की विशिष्ट कहानी के रूप में स्थानीयकृत नहीं हो पाया है।

जब एक सांझेदार का दबदबा हो और दूसरा उसमें अपनी जगह बना रहा हो, तो यह सवाल अपने आप हल हो जाता है कि 'नेतृत्व किसके हाथ में है'। कांग्रेस के लिए एक व्यावहारिक रास्ता यह है कि वह अनुशासित सहायक साझेदार बनकर पी.डी.ए. गठबंधन को उन सीटों पर मजबूत करे, जहां वह लाभ पहुंचा सकती है, जैसे कि ब्राह्मण बहुल और शहरी क्षेत्र, न कि सीटों के बंटवारे में समानता पर जोर

दे। अतिवादी रवैया पहले से ही नाजुक भाजपा विरोधी गठबंधन को और भी कमजोर कर सकता है।

ऐसा नहीं कि कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है, ऐसा राष्ट्रीय पार्टी का प्रतीकात्मक महत्व तो होता ही है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे विविधतापूर्ण राज्य में यह महत्व बराबर का प्रभाव नहीं होता। सपा के पास कार्यकर्ताओं की स्थिरता है, द्विध्रुवीय समीकरण है, जो भाजपा विरोधी बचे हुए वोटों को अपनी ओर खींचता है और यादव और सार्वजनिक विवरण विभाग के माध्यम से राजनीतिक परिदृश्य पर उसका नियंत्रण है। निष्पक्ष विश्लेषण में, यह एक ऐसा गठबंधन है, जिसमें एक सहयोगी अकेले टिक सकता है और दूसरा नहीं तथा यही अर्संतुलन कांग्रेस के लिए सीटों और गठबंधन में उसकी स्थिति को तय करेगा।

कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा विकल्प यही है कि वह समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े और सीटों की मांग बढ़ा-चढ़ाकर न करे, बल्कि यथार्थवादी रखे, यानी सीमित सीटों पर ही संसाधन केंद्रित करे। कम सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करने से दो फायदे होंगे-एक तो 2029 के लिए सीट बंटवारे की बातचीत में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी और दूसरा, पार्टी को मौजूदा विधायकों का एक मजबूत समूह मिलेगा। इस तरह की जमीनी उपस्थिति केंद्रीय नेतृत्व की दृश्यता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।



गामागोरी । भारत की सेलर नेत्रा कुमार ने महिलाओं की डिग्री में ब्रॉन्ज मेडल जीता। काइयोह यॉट हार्वर में दो रेस की फाइनल सीरीज के बाद नेत्रा ने 14 पॉइंट्स के साथ फिनिश किया। थाईलैंड की सोफिया मोटगोमरी ने पांच पॉइंट्स के साथ

गोल्ड जीता, जबकि सिंगापुर की जानिया एंग ने 13 पॉइंट्स के साथ सिल्वर जीता। एशियन गेम्स 2026 में भारत का सेलिंग में यह तीसरा मेडल है। इससे पहले पुरुषों की स्किफ में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिकल नोबल ने सिल्वर और महिलाओं की स्किफ में

रचा इतिहास

नेत्रा ने महिलाओं की डिग्री सेलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता

जीतकर (एक पॉइंट जोड़कर) जवाब दिया, जिससे वह ओवरऑल तीसरे स्थान पर पहुंच गई। नेत्रा 14 नेट पॉइंट्स (क्वालीफिकेशन सीरीज और फाइनल से सात-सात पॉइंट्स) के साथ हांगकांग की स्टेफनी नॉर्टन के बराबर रही, लेकिन पूरी सीरीज में बेहतर हेड-टू-हेड रिकॉर्ड रखने के बाद टाई-ब्रेक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेत्रा ने 2021 में ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय महिला सेलर बनकर इतिहास रचा था।



नागोया । एशियन गेम्स 2026 में नागोया सिटी मिजुहो पार्क जिम्नेजियम में शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में जापान से 0-2 से हारकर भारतीय पुरुष क्वाइट टीम को सेपकटकराव में ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। मालेमंगनबा सिंह सोरोखाइबाम, राम कुमार शर्मा, बॉबी कुमार और आकाश युननाम (लोखोन सिंह एलांगबाम और टेकोंग अरुण सक्स) की भारतीय क्वाइट सेमीफाइनल में

युकी सातो, रयोंटा हारुहारा, वतारू नारवा और योंटा इचिकावा (सेया ताकानो और तोशिताका नाइतो सक्स) की जापानी क्वाइट से 12-15, 13-15 के करीबी अंतर से हार गई। एशियाड में यह भारत का सेपक टकरों में सिर्फ तीसरा मेडल है। भारत ने 2018 जकार्ता गेम्स में पुरुषों की टीम रेगु में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और उसके बाद 2023 हांगझोऊ गेम्स में महिलाओं की टीम रेगु में ब्रॉन्ज मेडल जीता

भारत के पुरुष क्वाइट ने सेपकटकराव में ब्रॉन्ज मेडल जीता

था। भारतीय पुरुषों की टीम ने तीनों मैच जीतकर ग्रुप ए में टॉप पर जगह बनाई। उसने लीग स्टेज में वर्ल्ड कप विनर म्यांमार को भी चौका दिया था और वियतनाम और लाओस को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इस बीच, भारतीय महिलाओं की टीम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई। वह अपने तीन मैचों में कोई जीत हासिल किए बिना ग्रुप ए में चौथे स्थान पर रही। महिलाओं के डबल्स में भारत अपने ग्रुप बी में चौथे स्थान पर रहा और खेले गए तीनों गेमों में से एक भी गेम नहीं जीत पाया।

भारतीय पुरुषों की रेगु टीम भी नॉकआउट में जगह बनाने में नाकाम रही और एक जीत और दो हार के साथ ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर रही।

संक्षिप्त

समाचार

एशियन गेम्स

रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत को सिल्वर, ओलंपिक कोटा से चूकी भारतीय टीम

ओकाजाकी । धीरज बोम्मादेवरा और कुमुकुम मोहोद की मिक्स्ड रिकर्व आर्चरी टीम को ओकाजाकी चुओ सोगो पार्क मल्टीपर्पस स्क्वायर में चीन के खिलाफ हुए फाइनल मुकाबले में हार के कारण सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। चीन ने गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया, जबकि दूसरे स्थान पर रही भारतीय टीम ओलंपिक कोटा पाने से चूक गई। रिकर्व तीरंदाजी में यह भारत का दूसरा मेडल है। महिला टीम ने शुक्रवार सुबह एशियन गेम्स में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। महिला टीम ने फाइनल में 10 बार की चैंपियन टीम दक्षिण कोरिया को हराया। मिक्स्ड टीम फाइनल में, भारत ने 9 और 8 के स्कोर से शुरुआत की, जबकि चीन ने 10 और 8 के स्कोर से जवाब दिया।



पुरुष रिकर्व टीम इवेंट में भारत को सिल्वर मेडल, फाइनल में दक्षिण कोरिया से मिली हार

ओकाजाकी । भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाजी टीम को शुक्रवार को ओकाजाकी चुओ सोगो पार्क मल्टीपर्पस स्क्वायर में फाइनल में नौ बार की चैंपियन दक्षिण कोरियाई टीम ने हरा दिया। हार के कारण भारतीय टीम को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। भारतीय टीम में शामिल नीरज चौहान,



यशदीप भोगे और धीरज बोम्मादेवरा की तिकड़ी को दक्षिण कोरिया की किम जे देओक, किम वूजिन और ली वूसोक की तिकड़ी ने 1-5 से हराया। पुरुषों के रिकर्व टीम इवेंट में यह भारत का लगातार दूसरा एशियन गेम्स सिल्वर मेडल है। भारतीय टीम को हांगझोऊ 2023 के फाइनल में भी दक्षिण कोरिया से हार का सामना करना पड़ा था। ओलंपियन बोम्मादेवरा उस सिल्वर मेडल जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे।

गीत के लिए खास है 3 अक्टूबर

1992 में जीता था विश्व पेशेवर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब

नई दिल्ली । गीत सेठी का नाम भारत के प्रसिद्ध बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ियों में शुमार है। 1990 के दशक में सेठी ने इस खेल में अपना दबदबा बनाया था। गीत सेठी का जन्म 17 अप्रैल, 1961 को दिल्ली में हुआ था। उनका पूरा नाम गीत श्रीराम सेठी है। अहमदाबाद में पले-बढ़े सेठी ने 13 साल की उम्र में बिलियर्ड्स खेलना शुरू किया



था। गुजरात स्पोर्ट्स क्लब में उनकी मुलाकात उस समय के एक बहुत ही सफल बिलियर्ड्स खिलाड़ी सतीश मेनन से हुई और उन्होंने उनसे महत्वपूर्ण टिप्स और मार्गदर्शन लिया। उन्होंने पहली बार 1982 में इंडियन नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में माइकल फरेरा को हराकर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई।

वनडे विश्वकप 2027 के ग्रुप घोषित, दो अक्टूबर से शुरू होगा टूर्नामेंट, एक ही ग्रुप में भारत पाकिस्तान



भारत-पाक एक ही ग्रुप में

विश्व कप के ग्रुप चरण में भारत और पाकिस्तान को ग्रुप ए में रखा गया है। इस ग्रुप में भारत और पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और क्वालिफायर-ए की टीम होगी।

ग्रुप ए

- अफगानिस्तान
- भारत
- जिम्बाब्वे
- ऑस्ट्रेलिया
- पाकिस्तान
- क्वालिफायर-ए

क्वालिफायर-ए और क्वालिफायर-बी की टीमों के नाम बाद में तय होंगे। 2027 विश्व कप के लिए 10 टीमों सीधे अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं, जबकि बाकी स्थान क्वालिफिकेशन प्रक्रिया से तय होंगे।

ग्रुप बी

- बांग्लादेश
- दक्षिण अफ्रीका
- न्यूजीलैंड
- इंग्लैंड
- श्रीलंका
- क्वालिफायर-बी

2027 विश्व कप में 14 टीमों, 12 वेन्यू और 57 मैच

वनडे विश्व कप 24 साल बाद अफ्रीकी धरती पर लौट रहा है। दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे इससे पहले 2003 विश्व कप की मेजबानी कर चुके हैं, जबकि नामीबिया पहली बार पुरुषों के सीनियर वनडे विश्व कप के लिए मेजबान देश के रूप में सामने होगा। टूर्नामेंट के लिए दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में कुल 12 वेन्यू तय किए गए हैं। इनमें दक्षिण अफ्रीका के आठ, जिम्बाब्वे के तीन और नामीबिया की राजधानी विंडहोक का एक वेन्यू शामिल है।

2023 और 2027 में क्या बदला?

- 2023 विश्व कप 10 टीमों शामिल थीं।
- सभी 10 टीमों ने एक ही लीग चरण में मुकाबले खेले।
- प्रत्येक टीम ने नौ लीग मैच खेले।
- अंक तालिका की शीर्ष चार टीमों सेमीफाइनल में पहुंचीं।
- कुल 48 मैच खेले गए।
- 2027 विश्व कप टीमों की संख्या बढ़ाकर 14 कर दी गई है।
- शुरुआत तीन टीमों की सुपर सीरीज से होगी।
- सुपर सीरीज की विजेता मुख्य ग्रुप चरण में पहुंचेगी।
- 12 टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा।
- ग्रुप चरण में 30 मुकाबले होंगे।
- दोनों ग्रुप से शीर्ष तीन-तीन टीमों के अलावा एक और टीम सुपर-7 में पहुंचेगी।
- सुपर-7 में सात टीमों 21 मुकाबले खेलेंगी।
- सुपर-7 की शीर्ष चार टीमों सेमीफाइनल खेलेंगी।
- कुल 57 मैच खेले जाएंगे।



सुपर-7 में होगा बड़ा मुकाबला

2027 विश्व कप के प्रारूप में सबसे बड़ा बदलाव सुपर-7 चरण है। इसमें सातों टीमों राउंड-रॉबिन आधार पर एक-दूसरे से भिड़ेगी। इस चरण में कुल 21 मैच खेले जाएंगे। सुपर-7 की अंक तालिका में शीर्ष चार स्थान पर रहने वाली टीमों सेमीफाइनल में पहुंचेगी। पहले स्थान वाली टीम चौथे स्थान वाली टीम से भिड़ेगी, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम तीसरे स्थान वाली टीम के खिलाफ खेलेंगी। दोनों सेमीफाइनल के विजेता फाइनल में खिताब के लिए आमने-सामने होंगे।

2023 विश्व कप में कैसा था प्रारूप?

भारत में खेले गए 2023 वनडे विश्व कप में कुल 10 टीमों शामिल थीं। सभी टीमों ने लीग चरण में एक-दूसरे के खिलाफ एक-एक मुकाबला खेला था। इस तरह प्रत्येक टीम ने नौ लीग मैच खेले और अंक तालिका की शीर्ष चार टीमों सीधे सेमीफाइनल में पहुंची थीं। इसके बाद दो सेमीफाइनल और फाइनल के साथ टूर्नामेंट समाप्त हुआ था। यानी 2023 में नॉकआउट से पहले सिर्फ एक लीग चरण था। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराकर 2023 विश्व कप का खिताब जीता था।

रोहित-कोहली के लिए अहम होगा मौका

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए 2027 वनडे विश्व कप अंतरराष्ट्रीय करियर को एक और विश्व कप खिताब के साथ यादगार बनाने का आखिरी मौका हो सकता है। रोहित शर्मा ने 2024 टी20 विश्व कप में भारत की खिताबी जीत को याद करते हुए



कहा था कि वह 50 ओवर के प्रारूप में भी उस अहसास को दोबारा महसूस करना चाहते हैं। रोहित ने कहा था कि भारत के लिए विश्व कप जीतना बेहद खास अहसास है। उन्होंने बताया कि उन्होंने टी20 प्रारूप में दो बार विश्व कप जीतने का अनुभव किया है। 2007 में वह महज 20 साल के युवा खिलाड़ी थे, जबकि 2024 में भारत ने लंबे अंतराल के बाद आईसीसी खिताब जीता। वहीं, विराट कोहली ने कहा कि 2027 विश्व कप भारत के लिए उनका आखिरी विश्व कप होगा और यही उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। कोहली ने कहा था कि वह मैदान पर अपना सब कुछ झोक देना चाहते हैं। उनका लक्ष्य विश्व कप जीतना है और इसके लिए वह हर संभव प्रयास करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच जीतना है।

10 अक्टूबर 2027

भारत-पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला

भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप चरण का मुकाबला 10 अक्टूबर 2027 को खेला जाएगा। विश्व कप के कार्यक्रम के सामने आने से पहले ही इस मुकाबले को लेकर प्रशंसकों में खास उत्सुकता थी। दोनों टीमों ग्रुप ए में हैं और नए प्रारूप के तहत ग्रुप चरण में दोनों का आमना-सामना होना तय है। भारत-पाकिस्तान की विश्व कप प्रतिद्वंद्विता का रिकॉर्ड भी भारतीय टीम के पक्ष में रहा है। दोनों के बीच वनडे विश्व कप में अब तक आठ मुकाबले खेले गए हैं और भारत ने सभी आठ मैच जीते हैं। 2023 विश्व कप में अहमदाबाद में हुई पिछली भिड़ंत में भारत ने पाकिस्तान को सात विकेट से हराया था। आईसीसी के मुताबिक यह विश्व कप में दोनों टीमों का आठवीं भिड़ंत थी और भारत ने सभी आठ मैच अपने नाम किए थे।

जापान मेरे लिए लकी है: लवलीना

मुझे जन्मदिन पर खुद को गिफ्ट देना था

मेडल जीतने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि मुझे अपने जन्मदिन पर खुद को गोल्ड मेडल गिफ्ट करना चाहिए। हार के बारे में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। यह बहुत मुश्किल फाइट थी। लेकिन मैं हमेशा सोच रही थी कि मुझे जीतना है।' उन्होंने कहा, 'कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद ऐसा नहीं था। मैं सिल्वर मेडल जीतकर बहुत खुश थी। एक एथलीट की जिंदगी में बहुत सी चीजें होती हैं—हार और चोटें, जिन्हें हमें संभालना होता है और आगे बढ़ना होता है। यह गोल्ड मेडल मेरे लिए बहुत जरूरी था।' लवलीना ने 3-2 से करीबी शुरुआती राउंड जीतने के बाद बाउट में दबदबा बनाया। उन्होंने अगले दो राउंड 4-1 के समान अंतर से

जीते और हांगझोऊ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने के बाद अपना दूसरा एशियन गेम्स मेडल जीता। पहले दो राउंड में आगे रहने के बाद 2026 एशियाड फाइनल में वह आखिरी राउंड में सावधान थीं। उन्होंने कहा, 'आखिरी राउंड बहुत मुश्किल था। विरोधी बहुत मजबूत थीं। मैं उसके साथ पहली बार खेल रही थी। इसलिए मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वह कैसे खेलेंगी। मैं खुद को मोटिवेट कर रही थी कि मुझे जीतना है। मैं हारना नहीं चाहती, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरी राउंड भी ऐसा ही था। मैंने पहले दो राउंड जीते और मैं सोच रही थी कि मुझे तीसरा राउंड भी जीतना है।' लवलीना ने कहा, 'मैं एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने आई थी। मैंने खुद को मोटिवेट किया कि मुझे मजबूत रहना है और जीतना है।



निशियो । लवलीना बोरोगहेन ने शुक्रवार को एशियन गेम्स 2026 में 75 किग्रा फाइनल में चीन की जियाई बाओ को हराकर गोल्ड मेडल जीता। यह गोल्ड मेडल बोरोगहेन के लिए यादगार है, क्योंकि यह उनके 29वें

जन्मदिन पर आया है। लवलीना एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली मैरी कॉम के बाद गोल्ड जीतने वाली दूसरी महिला बॉक्सर बन गई हैं। लवलीना ने चीन की मुकेबज को 5-0 के सर्वसम्मत स्कोर से हराया। गोल्ड